सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 265, नई दिल्ली । बुधवार, 04 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

समुद्र में चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, समुद्र अपनी शांति कभी नहीं छोड़ता

03 मोहल्ला बसों के साथ दिल्ली में परिवहन क्रांति 2.0 की शुरुआत
06 भारतीय स्कूल डिजिटल साक्षरता और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से कैसे निपट
08 *चक्रवात फेंगल: तमिलनाडु और केरल में भारी तबाही

मोहल्ला बसों के साथ दिल्ली में परिवहन क्रांति 2.0 की शुरुआत- अगले 2 सप्ताह में दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी 150 शानदार मोहल्ला बसें

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आप सरकार ने एक बार फिर दिल्लीवालों से किया अपना वादा निभाया है। मोहल्ला बसों के साथ दिल्ली में परिवहन क्रांति 2.0 की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में अपने 2 सप्ताह के भीतर 150 मोहल्ला बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा। इस बाबत मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को कुशक नाला डिपो में मोहल्ला बसों का निरीक्षण किया। सीएम ने यहाँ बसों में लोगों के लिए मौजूद सुविधाओं का निरीक्षण किया, बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की और ख़ुद अधिकारियों के साथ बस में सफ़र भी किया। इस मौके पर सीएम आतिशी ने कहा कि, ₹मोहल्ला बसों के साथ दिल्ली की सड़कों पर परिवहन क्रांति के नए दौर की शुरुआत होगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में आई ये मोहल्ला दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर साबित होंगी।

सीएम आतिशी ने कहा कि, ₹आज हम कुशक नाला इलेक्ट्रिक बस डिपो पर मोहल्ला बसों का निरीक्षण करने आए है। इस डिपो में इन 9 मीटर की 150 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसों की पहली खेप आ चुकी है।

उन्होंने कहा कि, इन बसों का 2 रूट पर निरीक्षण भी हो चुका है। ये 150 बसें आने वाले 2 सप्ताह में दिल्ली की सड़कों पर उतर जायेंगी। जिन भीड़भाड़ वाले इलाकों में 12 मीटर की बड़ी बसें नहीं जा पाती है, उन इलाकों में अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में लाई गई ये मोहल्ला बसें गेम चेंजर साबित होंगी।

सीएम आतिशी ने साझा किया कि,

दिल्ली में हमेशा से ट्रांसपोर्ट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर 2140 सड़कें उतरेंगी। ये सभी बसें पूरी तरह वातानुकूलित है। बस पैनिक बटन, सीसीटीवी और जीपीएस से लैस है। मात्र मिनट की चार्जिंग के साथ ये बसें 200 किमी तक चल सकती है।

उन्होंने कहा कि, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्लीवालों को सुविधा देने का काम ₹आप₹ सरकार पिछले 10 सालों से कर रही है। डीटीसी बसों में आम परिवार के लोग जाते है। उन्हें सबसे शानदार सुविधाएं मिले ये अरविंद केजरीवाल का विज़न है और आप सरकार लगातार इसपर काम कर रही है।

बता दे कि, नौ मीटर लंबी ये बसें इलेक्ट्रिक बैटरी से संचालित होती हैं और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में चलाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जहां दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की 12 मीटर लंबी मानक बसें नहीं चल सकती थीं, जैसे कि भीड़भाड़ वाले मोहल्ले और तंग गलियां। ये बसें मेट्रो स्टेशनों जैसे महत्वपूर्ण परिवहन बिंदुओं को बेहतर तरीके से जोड़ने में भी मदद करेंगी।

यह न केवल लोगो के समय और पैसे की बचत करेगी, बल्कि उन्हें ऑटो रिक्शा लेने या अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई बस रूट बदलने की आवश्यकता भी समाप्त कर देगी

मोहल्ला बस 196 किलोवाट की कुल क्षमता वाले छह बैटरी पैक से सुसज्जित है, जो 45 मिनट की चार्जिंग के साथ 200+ किमी की रेंज प्रदान करती है ।9 मीटर की इन मोहल्ला बसों में 23 यात्री सीटें और 13 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता है।

आसानी से पहचान के लिए मोहल्ला बसों को हरे रंग का रखा गया है। मोहल्ला बसों में 25% सीटें (6 सीटें) गुलाबी रंग की हैं, जो विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए आरक्षित हैं।

मोहल्ला बस योजना का लक्ष्य 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा दिल्लीवासियों को उनके घर के आसपास फीडर बस सेवाएं प्रदान करना है ।दिल्ली सरकार की योजना 2025 तक कुल 2,140 ऐसी बसें शुरू करने की है, जो विशेष रूप से सीमित सड़क चौड़ाई या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए होंगी।

दिल्ली सरकार ने मोहल्ला बसों की पार्किंग और रखरखाव के लिए पूरी दिल्ली में 16 डिपो बनाए हैं।

*पूर्वी ज़ोन*गाजीपुर डिपो में 60 मोहल्ला बसें होंगी ।ईस्ट विनोद नगर में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

*पश्चिम ज़ोन*द्वारका मुख्य डिपो में 40 मोहल्ला बसें होंगी ।द्वारका सेक्टर 2 डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी। केशोपुर डिपो 180 मोहल्ला बसों को समायोजित करेगा ।पीरागढ़ी डिपो में 135 मोहल्ला बसें होंगी। शादीपुर डिपो में 230 मोहल्ला बसें होंगी।. द्वारका सेक्टर 9 डिपो में 20 मोहल्ला बसें होंगी।

दक्षिण ज़ोन कुशक नाला डिपो में 350 मोहल्ला बसें होंगी ।अंबेडकर नगर डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

*उत्तरी ज़ोन*मुंडका डिपो में 60 मोहल्ला बसें होंगी।

नांगलोई डीएमआरसी में 60 मोहल्ला बसें होंगी ।नांगलोई डीटीसी डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी। रिठाला डिपो में 70 मोहल्ला बसें होंगी ।कोहाट एन्क्लेव डिपो में 35 मोहल्ला बसें होंगी ।नरेला बस डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

मोहल्ला बस योजना दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन और लास्ट माईल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी बसों को परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हर्ष मल्होत्रा केन्द्रीय परिवहन राज्य मंत्री द्वारा मिला आश्वासन

जल्द ही बुराड़ी वाहन जांच शाखा में वाहनों की जांच का कार्य होगा शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। बुराड़ी वाहन जांच शाखा में वाहनों के पुनः जांच शुरू कराने के लिए परिवहन क्षेत्र में जुड़े वाहन मालिकों द्वारा हर्ष मल्होत्रा केन्द्रीय परिवहन राज्य मंत्री से उनके निवास पर मुलाकात कर उन्हें दिल्ली परिवहन आयुक्त द्वारा बुराड़ी वाहन जांच शाखा से वाहनों को जांच के लिए झूलझूली वाहन शाखा में स्थानांतरित करने की बात बताई ओर साथ ही उस कारण होने वाली परेशानियों से अवगत करवाया।

इस मुलाकात में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व महापौर अवतार सिंह, केके छाबड़ा, राजू कक्कड़ और देवेंद्र यादव थे।

अवतार सिंह के द्वारा केन्द्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के समक्ष ब्यौरे और सबूतों के साथ इस आदेश से उत्पन्न परेशानियों को उजागर किया गया।

अवतार सिंह ने हर्ष मल्होत्रा को बताया की कैसे एक बिना सोचे समझे किए गए परिवहन आयुक्त के आदेश से दिल्ली के तमाम व्यवसायिक वाहन मालिकों / चालकों और इस श्रेणी में जुड़े अन्य व्यवसायियों को बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया गया।

अवतार सिंह ने हर्ष मल्होत्रा को बताया की इसी प्रकार का आदेश पूर्व मुख्यमंत्री ने भी साल 2018 में किया था और कुछ ही महीनों में स्वयं ही वापिस के आदेश जारी किए थे।

अवतार सिंह ने बताया की पूर्व में की जा चुकी गलती को सुधार किए बिना फ़िर से करने का अर्ध स्पष्ट करता है की व्यवसायिक वाहन मालिकों को इससे कितनी परेशानी हो रही है।

अंत में सभी व्यवसायिक वाहनों के मालिकों/चालकों और इस क्षेत्र में जुड़े व्यवसायियों की तरफ से लिखित और मौखिक प्रार्थना कर जब तक दिल्ली में अन्य ऑटोमेटिक वाहन जांच शाखाएं नहीं खुल जाती और झूलझूली में सुरक्षा मुहैया नहीं होती तब तक वाहनों की जांच वापिस बुराड़ी वाहन जांच शाखा में शुरू कराने का आग्रेय किया।

केन्द्रीय वाहन राज्य मंत्री ने सभी को आश्वासन दिया की वह दिल्ली परिवहन आयुक्त से इस बाबत बाट कर बुराड़ी वाहन जांच शाखा में वापिस वाहनों की जांच जल्द शूरू करवाएंगे।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: सफर का वक्त घटकर होगा 2.5 घंटे, जनवरी 2025 से खुलेगा नया राजमार्ग

झशंका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड
न्यूज परिवहन विशेष

नई दिल्ली। दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा को तेज़ और सुविधाजनक बनाने वाला दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जनवरी 2025 से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह 212 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा के समय को घटाएगा, बल्कि सफर को सुरक्षित और सुगम भी बनाएगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपये है।

6.5 घंटे का सफर होगा सिर्फ 2.5 घंटे*

इस नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच की यात्रा का समय 6.5 घंटे से घटकर महज 2.5 घंटे रह जाएगा। यह सड़क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम, मंडोला, बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगी।

डेटकाली टनल: परियोजना का प्रमुख आकर्षण

देहरादून के पास बन रही *डेटकाली टनल* इस परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है। 340 मीटर लंबी यह तीन-लेन सुरंग लगभग *1995 करोड़ रुपये* की लागत से बनाई जा रही है।

वन्यजीवों के लिए विशेष प्रावधान*

इस एक्सप्रेसवे को पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।

गणेशपुर से देहरादून तक का हिस्सा वन्यजीवों के लिए सुरक्षित बनाया गया है।

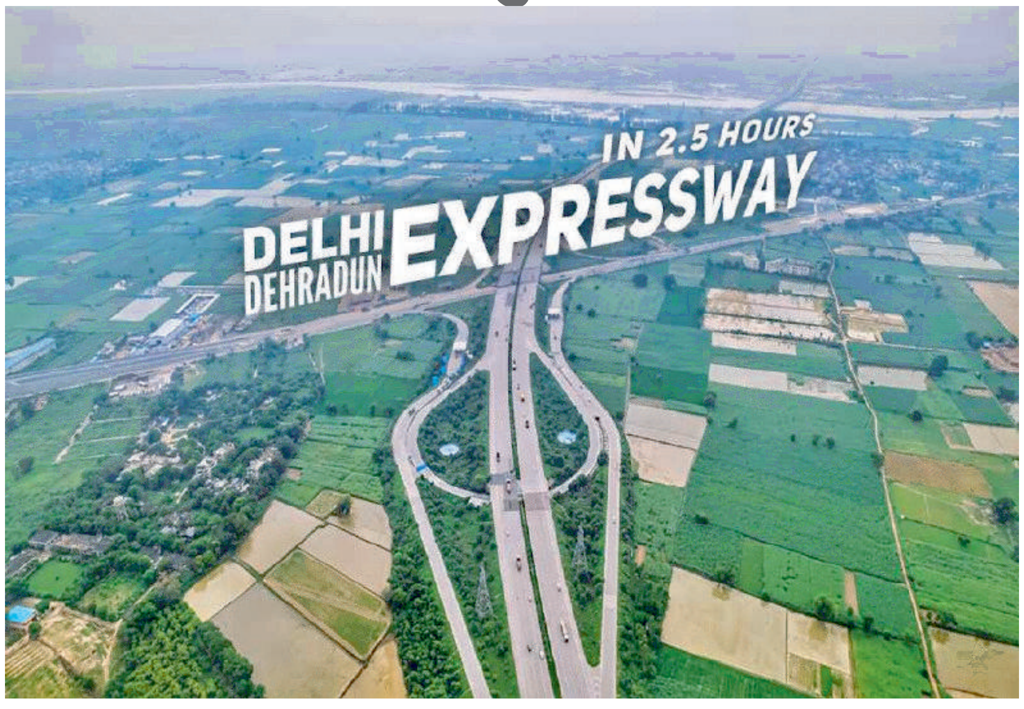

इसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, 6 एनिमल अंडरपास और 2 एलिफेंट अंडरपास शामिल हैं। इसके अलावा, 2 बड़े और 13 छोटे पुल भी बनाए गए हैं।

*** अन्य सुविधाएं और संरचनाएं***

- *113 वाहन अंडरपास (VUP)
- 76 किलोमीटर सर्विस रोड
- 62 बस शेल्टर
- 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स
- 29 किलोमीटर एलिवेटेड रोड

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव*

यह एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोज़गार के नए अवसर भी पैदा करेगा। इसके अलावा, क्षेत्र में पलायन की समस्या पर भी नियंत्रण पाने में यह मददगार साबित होगा।

सुरक्षा और संरचना का ध्यान

परियोजना में उन्नत सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। सड़क की चौड़ाई छह लेन रखी गई है, जिसे भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना में यात्रियों और वन्यजीवों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे न केवल यात्री अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी नया आयाम देगा। यह परियोजना पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

जनवरी 2025 से शुरू होने वाले इस एक्सप्रेसवे का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

प्रदूषण रोकने के लिए पहली बार, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NCR जिलों के DCP संग बनाई टास्क फोर्स; करेगी ये काम

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण रोकने के लिए पहली बार NCR जिलों के DCP के साथ संयुक्त टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के छह जिलों के ट्रैफिक डीसीपी शामिल हैं। इसका उद्देश्य GRAP के चौथे चरण में प्रतिबंधित वाहनों को दिल्ली की सीमा तक पहुंचने से पहले ही रोकना और चालान करना है।

नई दिल्ली। ग्रेडेड रिस्पॉंस एक्शन प्लान (ग्रेप, GRAP) के चौथे चरण में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के निर्देश पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें पड़ोसी राज्यों हरियाणा और यूपी के छह जिले के ट्रैफिक डीसीपी भी शामिल हैं। टास्क फोर्स का गठन 30 नवंबर को किया गया था।

संयुक्त टास्क फोर्स में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) के सात डीसीपी व पड़ोसी राज्यों के छह जिले के ट्रैफिक डीसीपी समेत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर को नोडल अधिकारी के तौर पर शामिल किया गया है। बेहतर तालमेल व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहली बार इस तरह का नियम बनाया गया है।

प्रतिबंधित वाहनों को एनसीआर के जिलों में रोका जाए

ग्रेप चार में प्रतिबंधित किए गए वाहनों को दिल्ली की सीमा तक पहुंचने से पहले ही पड़ोसी राज्यों के विभिन्न जिले में रोका जा सके, इसलिए संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सीमाओं पर बैनर व संयुक्त पिकेट लगाकर पुलिस 15 साल पुराने पेट्रोल और दस साल पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने के अलावा ग्रेप चार में प्रतिबंधित वाहनों का चालान कर रही है।

ट्रैफिक पुलिस का बना है अलग से वॉट्सऐप ग्रुप

दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के ट्रैफिक इंस्पेक्टर जिनकी ड्यूटी सीमाओं पर है उनके लिए एक वॉट्सऐप ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। इस ग्रुप में सीमाओं पर चेकिंग से संबंधित तस्वीरें डाली जाती हैं। साथ ही आला अधिकारी किसी मसले पर निर्देश देते हैं।

“बांग्लादेश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यक”

अगर बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो, शांति और भाईचारा क़याम करने के लिए उन्हें एक नया स्वतंत्र देश बनाकर दे देना चाहिए

आगरा, संजय साग़र सिंह। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यकों की असुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जनपद के समाजसेवीयों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो, शांति और भाईचारा क़याम करने के लिए उन्हें एक नया स्वतंत्र देश बनाकर दे देना चाहिए। एक नया स्वतंत्र देश देना विश्व में शांति और भाईचारा क़ायम रखने में एक बहुत बड़ा और अल्पसंख्यकों के हित में सराहनीय कदम होगा। आज़ बांग्लादेश में सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता हैं। बांग्लादेश की सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या को हल करना ही वहां के असुरक्षित हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर होगा। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार से सामाजिक समरसता और भाईचारा क़ायम करते हुए सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का आग्रह किया।

अगर बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो, उनके लिए एक नया स्वतंत्र देश बनाकर दे देना चाहिए : डॉ उमेश शर्मा

अखिल भारतीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष-डॉ उमेश शर्मा ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश सरकार से इसे रोकने का आग्रह करता हूं। बांग्लादेश के करोड़ हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यको को समुंदर में नहीं फेंका जा सकता है। उन्हें बांग्लादेश देश की सरकार को करोड़ हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यको के साथ भाईचारा कायम रखते हुए समान व्यवहार करना चाहिए। बांग्लादेश देश करोड़ हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यको का भी देश है। वह पवित्र मंदिरों को तोड़ा जा रहा हैं और साधु संतों को बेबजह जेल में डाला जा रहा हैं। बेकसूर महिलाओं और मासूर बच्चों पर अमानवीय अत्याचार कर उन्हें मारा जा रहा हैं। बांग्लादेश सरकार, सेना, पुलिस और प्रशासन को वहां रह रहे करोड़ हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यको की भलाई और उन्हें शैतानों से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर बांग्लादेश की सरकार, सेना, पुलिस और प्रशासन करोड़ हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यको की सुरक्षा नहीं कर सकता तो, शांति और भाईचारा क़ायम रखते हुए उनके लिए एक नया स्वतंत्र देश बनाकर दे देना चाहिए।

एक नया स्वतंत्र देश देना भाईचारा क़ायम रखने में एक बहुत बड़ा और अल्पसंख्यकों के हित में सराहनीय कदम होगा : वरिष्ठ समाजसेवी अरविन्द कुमार एडवोकेट

वरिष्ठ समाजसेवी अरविन्द कुमार एडवोकेट ने बांग्लादेश में विभिन्न धर्मों के बीच फैलाई जा रही नफरत को समाप्त करने और लोगों को फिर से भाईचारा और शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्राथना करते हुए उन्होंने बांग्लादेश के धार्मिक स्थलों पर किए जा रहे आक्रमण को समस्याजनक बताया और कहा, ₹हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि नफरत फैलाने वाले अपने उद्देश्यों में सफल न हों। श्री अरविन्द ने आगे कहा कि मैं बांग्लादेश की सरकार से देश में इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश देश के क़ानून में धर्म और लोगों की भाषा में कोई अंतर नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। अगर बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें एक नया स्वतंत्र देश प्रदान किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाना और वहां की सरकार की जिम्मेदारी मानना उचित है, क्योंकि यदि बांग्लादेश अपनी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों, की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो यह देश के लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करता है। यदि बांग्लादेश की सरकार, सेना, पुलिस और वहां का प्रशासन मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं कर सकती, तो किसी अन्य समाधान की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, एक नया स्वतंत्र देश देना भाईचारा क़ायम रखने में एक बहुत बड़ा और अल्पसंख्यकों के हित में सराहनीय कदम होगा, जो न केवल बांग्लादेश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी सराहनीय मुद्दा बनेगा। आज़ बांग्लादेश में सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता हैं, साथ ही बांग्लादेश की सरकार से यह अपेक्षाएं भी हैं कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हों।”

यह समस्या बांग्लादेश के व्यापार और विकास के रास्ते में कितना बड़ा अवरोध उत्पन्न करेगा, इसकी वर्तमान सरकार कल्पना भी नहीं कर सकती : वरिष्ठ समाजसेवी चन्द्रवीर फौजदार

वरिष्ठ समाजसेवी चन्द्रवीर फौजदार ने कहा, बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा संकट यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदू, बौद्ध, ईसाई आदि अल्पसंख्यक इस समय कट्टरपंथियों के हमलों और हिंसा का शिकार हो रहे हैं। मंदिरों पर हमले, हिंदू व्यापारियों और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना, यह सब बांग्लादेश की सामूहिक और सांस्कृतिक धरोहर को ध्वस्त करने की दिशा में बढ़ते कदम हैं। जहां एक समय इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता एकता की प्रतीक थी, वहीं अब यह कट्टरपंथ के संकट में फंसता जा रहा है। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए न केवल एक आंतरिक संकट है, बल्कि व्यापार, उसकी विदेश नीति और वैश्विक छवि पर भी बहुत खराब असर डाल रही है, खासकर यह कट्टरपंथी रुझान और मानवाधिकारों का उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के खुलकर सामने आ गया हैं, और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, इससे कारण बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंध इस समय बहुत खराब हो रहे हैं, इसका व्यापक असर बांग्लादेश के कारोबार पर भी पड़ेगा और वो भी जल्द ही ग़रीबी, भुखमरी और कंगाली की कगार पर आ जायेगा। अगर जल्द ही बांग्लादेश अपनी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो यह देश के आर्थिक विकास एवं व्यापार के लिए खतरे की घंटी साबित होंगी।₹

अंत में उन्होंने कहा, ₹यदि बांग्लादेश अपने संविधानिक और सामाजिक मूल्यों की रक्षा नहीं करता, तो यह न केवल अपने व्यापार, तरक्की, आंतरिक विकास को प्रभावित करेगा, बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि और सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि बांग्लादेश सरकार जल्द ही इस स्थिति को संभाले और सभी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों, की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए अगर बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की नहीं कर सकती तो उन्हें एक नया स्वतंत्र देश प्रदान किया जाना चाहिए।

बांग्लादेश की सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या को हल करना ही वहां के अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर होगा : समाजसेवी पंकज जैन

समाजसेवी पंकज जैन ने बांग्लादेश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते कहा, ₹बांग्लादेश, जो रबींद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसे कवियों की धरती है। भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और समरसता का चेहरा, जो स्वतंत्रता से लेकर अब तक बांग्लादेश ने बनाये रखा था, वह संविधानिक विरासत इस समय बिखर गयी है। आज वहां अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से यहां कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा जहां अल्पसंख्यक अपने आपको इतना असुरक्षित महसूस करते हों। बांग्लादेश की सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करना ही वहां के अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर होगा, अन्यथा बहुत देर हो जायेगी। अंत में, समरसता तथा सौहार्द जिंदगी का रास्ता है, हिंसा कोई मार्ग नहीं है। बांग्लादेश में इन दिनों जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस कारण इसका आधारभूत ढांचा चरमरा रहा है और यह उसके व्यापार और विकास के रास्ते में कितना बड़ा अवरोध उत्पन्न करेगा, इसकी बांग्लादेश कि वर्तमान सरकार कल्पना भी नहीं कर सकती, यह स्थिति स्वयं बंगाल देश के लिए भी खतरे की घंटी है। इसलिए अगर बांग्लादेश देश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो, उनके लिए एक नया स्वतंत्र देश बनाकर दे देना चाहिए।”

भाईचारा, समरसता तथा सौहार्द शांति का रास्ता है, हिंसा कोई मार्ग नहीं : ठाकुर संजीव कुमार सिंह

अगर बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो, उनके लिए एक नया स्वतंत्र देश बनाकर दे देना चाहिए

नई दिल्ली, संजय साग़र सिंह। विशेष रूप से वहां के अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ते असुरक्षा और धार्मिक कट्टरपंथ के असर पर एवं बांग्लादेश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ठाकुर संजीव कुमार सिंह (राष्ट्रीय नेता कांग्रेस एआइसीसी एवं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया) ने कहा, ₹बांग्लादेश, जो रबींद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसे कवियों की धरती है। भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और समरसता का चेहरा, जो स्वतंत्रता से लेकर अब तक बांग्लादेश ने बनाये रखा था और एक लोकतांत्रिक और समावेशी समाज बनाने का सपना था। उनका उद्देश्य एक समान और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, लेकिन हालिया घटनाओं ने इस सपने को धुंधला कर दिया है। पूरा विश्व आज देख रहा हैं कि वह संविधानिक विरासत इस समय पूरी तरह बिखर गयी है। आज वहां अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से बांग्लादेश में कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा जहां अल्पसंख्यक अपने आपको इतना असुरक्षित महसूस करते हों। इसलिए अगर बांग्लादेश देश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो, उनके लिए एक नया स्वतंत्र देश बनाकर दे देना चाहिए। एक नया स्वतंत्र देश देना एक बहुत बड़ा और अल्पसंख्यकों के हित में सराहनीय कदम होगा, जो न केवल बांग्लादेश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी सराहनीय मुद्दा बनेगा। बांग्लादेश की सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या को हल करना ही वहां के हिन्दू बौद्ध ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर होगा, अन्यथा बहुत देर हो जायेगी।

उन्होंने कहा, समरसता तथा सौहार्द जिंदगी का रास्ता है, हिंसा कोई मार्ग नहीं है। बांग्लादेश में शांति, समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता हैं। यदि बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यको की संविधानिक और सामाजिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकता, तो यह न केवल उनके व्यापार, तरक्की, आंतरिक विकास को प्रभावित करेगा, बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि और सुरक्षा को भी खतरे में डाल देगा। इसलिए यह जरूरी है कि बांग्लादेश सरकार जल्द ही इस स्थिति को संभाले और सभी नागरिकों, विशेषकर हिन्दू बौद्ध ईसाई अल्पसंख्यकों, की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी दे।

अंत में, श्री सिंह ने कहा, आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाना और इसे वहां की सरकार की जिम्मेदारी मानना उचित है, क्योंकि यदि बांग्लादेश अपनी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों, की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो बांग्लादेश के लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा होगा। मंदिरों पर हमले, हिंदू व्यापारियों और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना, मासूम बच्चों और महिलाओं को मरना, यह सब बांग्लादेश की सामूहिक और सांस्कृतिक धरोहर को ध्वस्त करने की दिशा में बढ़ते कदम हैं। जहां एक समय इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता एकता की प्रतीक थी, वहीं आज की खतरनाक स्थिति बांग्लादेश के लिए न केवल एक आंतरिक संकट है, बल्कि व्यापार, उसकी विदेश नीति और वैश्विक छवि पर भी बहुत असर डाल रही है, खासकर यह कट्टरपंथी रुझान और मानवाधिकारों का उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के खुलकर सामने आ गया हैं, और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, इससे कारण बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंध इस समय बहुत खराब हो रहे हैं, जिसका असर आने वाले समय में बांग्लादेश के विकास और व्यापार पर पड़ेगा। अगर जल्द ही बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो यह बांग्लादेश के आर्थिक विकास एवं व्यापार के लिए खतरे की घंटी है।

सिजेरियन सेक्शन के बाद खाद्य पदार्थ और परहेज

डॉ. प्रियंका सौरभ

बहुत सी सिजेरियन डिलीवरी, गर्भावस्था की कुछ जटिलताओं या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण की जाती है। सी-सेक्शन प्रक्रिया ज़्यादातर महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण और अप्रिय हो सकती है और यह मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाली हो सकती है। प्रक्रिया से उबरने के लिए माँ को भरपूर आराम और सख्त आहार की आवश्यकता होती है। सी-सेक्शन के बाद पहले कुछ हफ़्तों के दौरान, माँ की पूरी तरह से निगरानी की जानी चाहिए और प्रसव के तनाव से मानसिक और शारीरिक रूप से उबरने में उसकी सहायता की जानी चाहिए। इसलिए, -सी सेक्शन के बाद उसे खाने के लिए उचित भोजन दिया जाना चाहिए।

चूंकि पहले कुछ महीनों के दौरान बच्चे के पोषण का मुख्य स्रोत स्तन का दूध होता है, इसलिए सीजेरियन सेक्शन के बाद माँ को अच्छा आहार लेना चाहिए। पर्याप्त आराम के साथ-साथ अच्छा आहार पेट की दीवार और गर्भाशय की उपचार प्रक्रिया को भी तेज कर सकता है, जो सी-सेक्शन के दौरान फट गए थे। उचित आहार माँ को गर्भावस्था के दौरान बढ़े हुए वज़न को कम करने में भी मदद कर सकता है।

सिजेरियन सेक्शन के बाद सही भोजन करना कुछ कारणों से बहुत महत्त्वपूर्ण है:

उपचार को बढ़ावा देता है: विटामिन, खनिज और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार आपके शरीर को तेजी से ठीक होने और सर्जरी से उबरने में मदद करता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है: स्वस्थ आहार खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है।

ऊर्जा प्रदान करता है: सी-सेक्शन के बाद, आपके शरीर को ठीक होने और अपने नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ आहार सुनिश्चित करता है कि आपके पास दोनों के लिए आवश्यक ऊर्जा है।

स्तनपान में सहायता: उच्च गुणवत्ता वाला स्तन दूध उपलब्ध कराने के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है, जो आपके बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है।

जटिलताओं को कम करता है: एक अच्छा आहार वज़न को नियंत्रित करने, कब्ज के जोखिम को कम करने और बेहतर पाचन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जो सर्जरी के बाद महत्त्वपूर्ण हैं।

मनोदशा में सुधार: संतुलित भोजन खाने से आपकी मनोदशा स्थिर रहती है और मानसिक स्पष्टता मिलती है, जिससे प्रसव के बाद भावनात्मक सुधार में सहायता मिलती है।

ऊतकों की मरम्मत में सहायक: प्रोटीन, विटामिन-सी और जिंक जैसे पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक हैं, जो आपके सर्जिकल घाव को अधिक प्रभावी ढंग से ठीक करने में मदद करते हैं।

सिजेरियन के बाद क्या खाना चाहिए?

सिजेरियन के बाद खाने योग्य खाद्य पदार्थों की सूची इस प्रकार है:

प्रोटीन और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ: प्रोटीन नए ऊतक कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे उपचार प्रक्रिया में तेजी आती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ सर्जरी के बाद ऊतकों को ठीक करने और मांसपेशियों की शक्ति को बनाए रखने में मदद करें। दूसरी ओर, कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मज़बूत बनाता है, मांसपेशियों को आराम देता है, रक्त के थक्के को बढ़ावा देता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। -सी सेक्शन के बाद अपने आहार में फलियाँ, अंडे आदि शामिल करें और ख़ुद को ठीक होते और मज़बूत होते देखें।

साबुत अनाज: ब्राउन ब्रेड, पास्ता और ब्राउन राइस सहित साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है। यह ऊर्जा के रखरखाव और स्तन दूध उत्पादन में सहायता करता है। आयरन, फाइबर और फोलिक एसिड सभी शिशुओं के लिए उनके शुरुआती विकास चरणों में महत्त्वपूर्ण पोषक तत्व हैं।

विटामिन और खनिज: विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है और ये ऊतक की मरम्मत में सहायता करते हैं। इसलिए, सीजेरियन सेक्शन के बाद आहार में इनका बहुत अच्छा समावेश हो सकता है। ये शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, जो स्नायुबंधन, नए निशान ऊतकों और त्वचा के निर्माण में सहायता करता है। पालक, ब्रोकली और मेथी के पत्तों जैसी सब्ज़ियों में आहार कैल्शियम और आयरन के अलावा विटामिन ए और-सी की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा, संतरे, पपीता, तरबूज, स्ट्रॉबेरी और अंगूर जैसे फलों में विटामिन-सी की मात्रा अधिक होती है और-सी सेक्शन के बाद खाने के लिए ये सबसे अच्छा भोजन है। ये फल और सब्ज़ियाँ संक्रमण की रोकथाम और प्रतिरक्षा निर्माण में सहायता करती हैं।

आयरन: लोहा बनाए रखता है हीमोग्लोबिन का स्तर शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है और प्रसव के दौरान खोए हुए रक्त की पूर्ति में मदद मिलती है। आयरन प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक से काम करने में मदद करता है। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों में अंडे की जर्दी, सीप, लाल मांस, गाय का जिगर और सूखे मेवे शामिल हैं। लेकिन, यह सलाह दी जाती है कि अधिक आयरन न लें क्योंकि इससे कब्ज हो सकता है। इसलिए, आयरन के सेवन के बारे में हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना उचित है।

सब्जियाँ: सिजेरियन के बाद खाने के लिए सब्जियाँ एक बेहतरीन विकल्प हैं। हरी सब्जियाँ नई माताओं के लिए फायदेमंद होती हैं क्योंकि उनमें आयरन, विटामिन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। पालक, बीन्स, कमल के तने, ब्रोकली और मेथी जैसी हरी सब्जियाँ डाइट प्लान में शामिल की जानी चाहिए। दूसरी ओर, आप मशरूम और गाजर से पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं।

सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद की अवधि जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उपचार में तेज़ी लाने के लिए भोजन पर नियंत्रण बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। सी-सेक्शन के बाद संतुलित आहार आपको सर्जरी से उबरने और आपको और आपके बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। डॉक्टर आमतौर पर सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद डाइट चार्ट तैयार करते हैं। डाइट चार्ट का सख़्ती से पालन करने के अलावा, आपको अपने खाने की आदतों पर भी नज़र रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सिजेरियन सेक्शन के बाद ठीक होने और पहले से ज़्यादा स्वस्थ बनने में मदद करेगी।

सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल, लंबा जीवन जीना है तो रखें इन बातों का ध्यान

सेहतमंद रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपकी सेहत को आपकी जीवनशैली काफी हद तक प्रभावित करती है। ऐसे में जरूरी है कि हेल्दी रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल का खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा होम्योपैथी भी आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकती है। आइए मुक्ता होम्योपैथी क्लीनिक नोएडा के डॉ. आशीष राजेन्द्र सिंह से जानते हैं होम्योपैथी के कुछ फायदे।

नई दिल्ली। तकनीक पर बढ़ती निर्भरता और आरामदायक दिनचर्या के कारण फिजिकल एक्टिविटी में कमी आ रही है, जिससे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर करना शुरू कर दिया है। भागती-दौड़ती जिंदगी और असंतुलित खानपान से अनेक तरह के स्वास्थ्य विकार जन्म ले रहे हैं। ऐसे में तनावमुक्त और अनुशासित दिनचर्या के महत्व को समझना जरूरी है, ताकि सेहतमंद जीवन के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

क्यों गंभीर हैं जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं

आज कई सारी बीमारी का कारण खराब जीवनशैली है। बीमारी के एक बार शुरू हो जाने के बाद लंबे समय तक प्रभाव शरीर को हर तरह के कमजोर कर देता है। हमें समझना होगा कि ये बीमारियां अचानक नहीं होतीं, बल्कि धीरे-धीरे शरीर पर असर डालती हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। आज लोग तेजी से डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा, हार्ट डिजीज और मानसिक तनाव की चपेट में आ रहे हैं। समय रहते इन सभी समस्याओं को रोका जा सकता है।

यह भी पढ़ें- सर्दियां आते ही क्यों बढ़ जाते हैं गले में खराश के मामले, डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके

बीमारी के मुख्य कारण

अनहेल्दी डाइट : तले-भुने भोजन, जंक फूड और फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। पौष्टिक आहार की कमी के कारण शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, जो कई रोगों के जन्म का कारण बनती है। शारीरिक गतिविधि की कमी, व्यस्त दिनचर्या और अधिकतर समय बैठकर काम करने की आदत से शरीर में मोटापा और अन्य समस्याएं बढ़ रही हैं। तनाव और मानसिक दबाव : अत्यधिक तनाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का भी कारण बनता है। अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना, कम सोना और असंतुलित कार्य प्रणाली शरीर को कमजोर बना देती है।

धूमपान और शराब: ये आदतें शरीर के अंगों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती हैं और दीर्घकालिक बीमारियों का कारण बनती हैं।

होम्योपैथी से रखें अपना ख्याल

होम्योपैथी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है, जो रोगी की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपचार करती है। यह शरीर के अंदरूनी संतुलन को बहाल करने में मदद करती है और इम्युनिटी को मजबूत बनाती है। जीवनशैली विकारों में होम्योपैथी न केवल लक्षणों को कम करती है, बल्कि बीमारी के मूल कारण पर भी काम करती है।

होम्योपैथी के लाभ

सुरक्षित और प्राकृतिक उपचार: होम्योपैथी के दुष्प्रभाव नहीं होते और यह शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखती है।

व्यक्तिगत उपचार: प्रत्येक रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार दवा दी जाती है।

दीर्घकालिक समाधान: होम्योपैथी लक्षणों को दबाने के बजाय समस्या की जड़ को ठीक करती है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना: यह शरीर की इम्युनिटी को मजबूत करती है, जिससे शरीर बीमारियों का सामना कर सके।

होम्योपैथी के साथ-साथ एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना भी जरूरी है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन से जीवनशैली विकारों को नियंत्रित किया जा सकता है।

जरूरी बातें

प्रतिदिन 30 मिनट योग या ध्यान करना चाहिए।

पर्याप्त फाइबर और प्रोटीनयुक्त आहार होना चाहिए।

जंक फूड और तले-भुने खाने से परहेज करना चाहिए।

कोई भी शारीरिक समस्या होने पर नियमित रूप से चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।

समग्र समाधान है होम्योपैथी

लाइफस्टाइल विकारों के लिए होम्योपैथी एक प्रभावी, सुरक्षित और समग्र समाधान है। यह शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। स

निर्माण के बाद भी इस कॉरिडोर पर शुरू नहीं हुई दिल्ली मेट्रो परिचालन की तीन माह पहले मिल गई थी परमीशन

संजय बाटला

जनकपुरी पश्चिम–कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच निर्मित मेट्रो कॉरिडोर परिचालन के लिए तैयार है लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है। सीएमआरएस से तीन महीने पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। इस कॉरिडोर के शुरू होने से मजेंटा लाइन का विस्तार होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इसके शुरू होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। फेज चार में जनकपुरी पश्चिम-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच निर्मित कॉरिडोर मेट्रो परिचालन के लिए तैयार है। सीएमआरएस (मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त) से मेट्रो परिचालन शुरू करने के लिए तीन महीने पहले स्वीकृति भी मिल चुकी है। लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी, DMRC) इस कॉरिडोर पर अब तक मेट्रो का परिचालन शुरू नहीं कर पाया है। डीएमआरसी ने मेट्रो परिचालन शुरू करने के लिए अब तक कोई तारीख भी घोषित नहीं की है।

विधानसभा चुनाव से शुरू पहले हो सकता है परिचालन

परिचालन शुरू होने में हो रही देरी का कारण डीएमआरसी ने स्पष्ट नहीं किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकता है।

29 किमी कॉरिडोर का हिस्सा

ढाई किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर फेज चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन का हिस्सा और यह वर्तमान मजेंटा लाइन की विस्तार परियोजना है। जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन की लंबाई करीब 29 किलोमीटर होगी।

इन स्टेशनों के बीच होगा परिचालन

मौजूदा समय में मजेंटा लाइन पर बॉटेनिकल गार्डन (Botanical Garden) से जनकपुरी पश्चिम के बीच मेट्रो का परिचालन होता है। जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच करीब ढाई किलोमीटर का भूमिगत कॉरिडोर बनकर तैयार होने से अगस्त में ही इस पर मेट्रो परिचालन शुरू करने की तैयारी थी।

कॉरिडोर पर सुरक्षा मानकों का हो चुका निरीक्षण

30 जुलाई को सीएमआरएस ने इस कॉरिडोर के मेट्रो ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म, कंट्रोल रूम इत्यादि के सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया था। डीएमआरसी के अनुसार, अगस्त के अंत में इस कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन शुरू करने की स्वीकृति सीएमआरएस से मिली थी। तब डीएमआरसी ने परिचालन के लिए जल्दी तारीख घोषित करने की बात कही थी लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ।

सरकार के इस कदम से यूनिवर्सिटी के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी-सीएम

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन (IGDTUW) के खातों का अगले पांच वर्षों के लिए सीएजी द्वारा ऑडिट करवाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने आईजीडीटीयूडब्ल्यू के खातों की अगले 5 सालों के लिए सीएजी द्वारा ऑडिट को मंजूरी दे दी है।

इस बाबत सीएम आतिशी ने कहा कि, सरकार के इस कदम से यूनिवर्सिटी के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ऑडिट के ज़रिए किसी भी प्रकार की अनियमितताओं और वित्तीय कुप्रबंधन को पहचान उसे दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि, शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ-साथ बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट "आप" सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में सीएजी ऑडिट सुनिश्चित करेगा की लोगों के टैक्स का का सही इस्तेमाल हो।

सीएम आतिशी ने कहा कि, सरकार का यह कदम यूनिवर्सिटी के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि, "आप" सरकार के लिए अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ-साथ बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा से प्राथमिकता रही है।

इस दिशा में सीएजी ऑडिट के जरिए यह सुनिश्चित होगा कि लोगों के टैक्स का का सही और बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो। साथ ही, इससे अनियमितताओं और वित्तीय कुप्रबंधन को भी दूर करने में भी मदद मिलेगी।"

सीएजी द्वारा ऑडिट कराए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि यूनिवर्सिटी के सभी वित्तीय लेन-देन और खर्चों की गहन जांच हो। यह प्रक्रिया न केवल वित्तीय कुप्रबंधन को रोकने में मदद करेगी बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता भी लाएगा। सीएजी ऑडिट से प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली ने हरिहरन का उनके 50 साल के संगीतमय मील के पत्थर पर प्यार से स्वागत किया

सुषमा रानी

दिल्ली। दिल्ली में संगीत प्रेमियों को एक शानदार शाम का आनंद मिला, जब पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित

हरिहरन ने एक विशेष संगीत कार्यक्रम के साथ अपनी पौराणिक संगीत यात्रा के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया।

हेल्प आर्टिस्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित, इस कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बेजोड़ संगीतमय भव्यता की एक रात के लिए संगीत प्रेमियों और

दिल्ली के उच्च पदस्थ अधिकारियों और अधिकारियों सहित गणमान्य लोगों को एक साथ लाया गया।

संगीत कार्यक्रम हरिहरन के शानदार करियर की एक यात्रा थी, जिसमें उनकी प्रतिष्ठित ग़ज़लें, भक्ति के टुकड़े और फिल्मी क्लासिक्स शामिल थे। रात अपने भावनात्मक चरम पर पहुंच गई जब हरिहरन ने अपना कालातीत क्लासिक ₹तू ही रे₹ प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसके बाद मील के पत्थर को चिह्नित करने के लिए जश्न मनाने के लिए केक काटने की रस्म हुई। उन्होंने शाम का समापन हार्दिक कृतज्ञता के साथ करते हुए कहा, "दिल्ली ने हमेशा मुझे खुले हाथों से अपनाया है। आज रात, आपके प्यार और ऊर्जा ने इस मील के पत्थर को और भी खास बना दिया है। मैं इस यात्रा का हिस्सा बनने और इसे अविस्मरणीय बनाने के लिए आप सभी का बहुत आभारी हूं।" शाम का मुख्य आकर्षण 50 समर्पित प्रशंसकों

को भावभीनी श्रद्धांजलि थी, जिन्हें हरिहरन द्वारा हस्ताक्षरित गिटार भेंट किए गए, जो संगीतकारों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के उनके जुनून का प्रतीक है। हेल्प आर्टिस्ट इंडिया फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने वाले कलाकारों का समर्थन करने और उनका जश्न मनाने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। हेल्प आर्टिस्ट इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक अशोक राजपूत ने संगीत में हरिहरन के अद्वितीय योगदान के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, "हरिहरन की 50 साल की विरासत हर कलाकार के लिए प्रेरणा है। हमें इस यात्रा का जश्न मनाने और दिल्ली में इस तरह के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लाने पर गर्व है। हमारा मिशन कलाकारों को वह मंच देना है जिसके वे हकदार हैं और यह सुनिश्चित करना है कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत फलती-फूलती रहे।" इवेंट डायरेक्टर फर्ज खान ने कहा, "दिल्ली ने इस कॉन्सर्ट में जो प्यार और ऊर्जा लाई, वह वास्तव में असाधारण थी। इस कार्यक्रम को एक शानदार सफलता बनाने और हमारे साथ हरिहरन जी जैसे दिग्गज का जश्न मनाने के लिए धन्यवाद।" कल रात का कार्यक्रम एक शानदार सफलता थी, जिसने देश की सबसे प्रिय आवाज़ों में से एक को श्रद्धांजलि दी। यह कॉन्सर्ट पुरानी यादों और जश्न का एक सहज मिश्रण था, जिसने सभी उम्र के प्रशंसकों को एक ऐसे दिग्गज को सम्मानित करने के लिए एक साथ लाया, जिनकी आवाज़ आधी सदी से भारत की सामूहिक आत्मा का हिस्सा रही है।

इनकी बर्खास्तगी ने महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और 11 हजार परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल दिया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राजसभा सदस्य संजय सिंह ने बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वालेंटियर्स के मुद्दे पर राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान अपनी बात रखने की अनुमति मांगी है। उन्होंने राज्यसभा के जेनरल सेक्रेटरी को दिए नोटिस में कहा है कि दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों को बहाल और नियमित करने की योजना तैयार करने का प्रस्ताव एलजी को भेजा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनकी बर्खास्तगी ने बस में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। साथ ही 11 हजार परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल दिया है।

संजय सिंह ने दिए नोटिस में कहा है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा और रोजगार से जुड़े एक अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली में लगभग 11,000 बस मार्शल, जिन्हें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था, उनको अचानक बिना किसी नोटिस या सूचना के नौकरी से हटा दिया गया।

संजय सिंह ने दिए नोटिस में कहा है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा और रोजगार से जुड़े एक अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली में लगभग 11,000 बस मार्शल, जिन्हें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था, उनको अचानक बिना किसी नोटिस या सूचना के नौकरी से हटा दिया गया। इन बस मार्शलों ने न केवल महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा भी की। उन्होंने कहा कि आज बस मार्शलों की बर्खास्तगी ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरे में डाल दिया है और लगभग 11,000 परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। दिल्ली सरकार ने इन्हें बहाल करने और नियमितीकरण की योजना तैयार करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कृपा करके मुझे इस अतिआवश्यक विषय पर शून्यकाल में अपनी बात रखने की अनुमति प्रदान करें।

केजरीवाल ने भरा वालेंटियर्स में जोश, मुफ्त की रेवड़ी को घर-घर पहुंचाने का दिया मंत्र

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रही, आम आदमी पार्टी की रणनीति वैसे -वैसे धारदार होती जा रही। आम आदमी पार्टी की रीढ़ माने जाने वाले वालेंटियर्स की इस चुनाव में भी महत्ती भूमिका है। इसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी बखूबी समझते हैं। इस कारण वह एक-एक वालेंटियर्स से सीधे संपर्क में हैं। उनसे विभिन्न माध्यमों से बात कर रहें। उन्हें सरकार के काम और खासकर दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त रेवड़ियों को घर-घर पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहे। इसके लिए अरविंद केजरीवाल पार्टी के सभी विंग के हर वालेंटियर्स से खुद सीधा संपर्क कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए महिला विंग के सभी वालेंटियर्स से संपर्क साधा। उन्हें मुफ्त को रेवाड़ी को घर-घर तक पहुंचाने का ना सिर्फ मंत्र दिया, बल्कि उनसे जमीनी हकीकत भी समझी। बातचीत के दौरान वालेंटियर्स ने केजरीवाल को बताया कि जनता फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है।

अरविंद केजरीवाल से बातचीत करने के लिए महिला विंग की अध्यक्ष सारिका चौधरी और उनके साथ 500 से अधिक महिला वालेंटियर्स इस वीडियो कॉल से जुड़ीं। महिला विंग ने अरविंद केजरीवाल को बताया कि वह घर-घर जा रही हैं और छोटी- छोटी बैठकें कर छह रेवड़ियों पर लोगों के साथ चर्चा कर रही हैं।

इस दौरान काफी महिला वालेंटियर ने अरविंद केजरीवाल से बात भी की। महिलाओं ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहें हैं। हम सभी आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। एक-एक व्यक्ति से बात कर आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। जनता को यह भी बता रहे हैं कि अगर ₹आपर₹ की सरकार चली गई तो उनको मिल रही मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का बस में सफर और बुजुर्गों की तीर्थयात्रा समेत अन्य सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जनता को यह भी बताया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली की खस्ता हाल को सुधारा है। दिल्ली की जनता को तमाम मुफ्त की सुविधाएं देने के साथ-साथ दिल्ली का बजट भी मुनाफे में बनाए रखा है। अगर दूसरी सरकार आ गई तो फिर दिल्ली 10 साल पहले वाली स्थिति में चली जाएगी। आपके स्कूल और अस्पताल का बेड़ा गर्क हो जाएगा।

महिला विंग के वालेंटियर्स ने बताया कि दिल्ली की जनता ₹आपर₹ सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से संतुष्ट है। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की सुविधाओं से बेहद खुश हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनें और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जनता को अरविंद केजरीवाल पर पूरा भरोसा है। जनता कह रही है कि जब तक आप हैं, उनका कोई भी काम नहीं रुकेगा।

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी जमीन पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सभी की इस मेहनत का परिणाम भी सुखद आयेगा। आप सभी इसी तरह मेहनत से लगे रहें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा बैठकें करने की कोशिश करें। कई टीम बनाकर अपनी एरिया में लोगों के साथ बैठक करें। इन बैठकों में छह रेवड़ियों को जनता को विस्तार से बताएं। छह रेवड़ियों के फायदे और उसने बंद होने के नुकसान भी बताएं, ताकि जनता सही निर्णय कर सके।

केजरीवाल ने वालेंटियर्स से उनका अनुभव और जमीनी हकीकत की जानकारी भी ली। साथ ही वालेंटियर्स की राय भी जानी। केजरीवाल ने कहा कि वालेंटियर्स हमारी रीढ़ है। उनकी मेहनत की बदौलत ही पार्टी आज इस मुकाम पर है। महिला वालेंटियर्स ने बताया कि दिल्ली केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने को बेताब है।

नोएडा एयरपोर्ट का रनवे तैयार, ट्रायल विमान उतरने का बस इंतजार

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस माह की 15 तारीख से कमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल पूरा होगा। वहीं पर अप्रैल महीने से यात्री देश-विदेश के लिए उड़ान सेवा का लाभ ले पाएंगे। एयरपोर्ट से साठ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान के साथ एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी। 21 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंद्रह दिसंबर तक कामर्शियल फ्लाइट का ट्रायल पूरा हो जाएगा। अप्रैल से यात्री नोएडा इंटरनेशनल पोर्ट से देश विदेश के लिए उड़ान सेवा का उपयोग शुरू कर देंगे। रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का काम पूरा हो चुका है।

आधुनिक तकनीकी से युक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारतीय संस्कृति के साथ डिजिटल यात्रा का अनुभव कराने के लिए अंतिम पड़ाव में है। एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने के बावजूद विमान लैंड व उड़ान भरने की क्षमता होगी।

देश में सबसे तेजी से विकसित होने के साथ नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बाद सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण का रिकार्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम दर्ज होगा।

21 नवंबर को पीएम ने किया था शिलान्यास

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2021 को किया था। निर्माण एजेंसी टाटा प्रोजेक्ट्स के चयन के बाद मई-जून 2022 में ही एयरपोर्ट का निर्माण वास्तव में तेजी के साथ धरातल पर शुरू हुआ। अप्रैल 2025 तक करीब तीन साल से कम समय में एयरपोर्ट से नियमित यात्री उड़ान के साथ सबसे तेजी से विकसित होने वाले एयरपोर्ट के रूप में इसका नाम दर्ज हो जाएगा।

साठ घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ान के साथ एयरपोर्ट की शुरुआत

एयरपोर्ट पर अप्रैल में शुरुआत से साठ घरेलू विमान सेवा होंगी। इंडिगो, अकासा के साथ इसके लिए अनुबंध हो चुका है। घरेलू सेवा में लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई, आदि प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा होगी। ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान के साथ दो कार्गो सेवा शुरू होगी।

देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर बनेगी पहचान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश में सबसे बड़ा होगा। एयरपोर्ट के लिए यीडा अधिसूचित क्षेत्र में 62 सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि आरक्षित है। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट दो रनवे के साथ विकसित किया जा रहा है। अप्रैल में एक रनवे के साथ इसकी शुरुआत होगी। यात्रियों की सालाना संख्या 1.20 करोड़ पहुंचने पर दूसरे रनवे का निर्माण शुरू हो जाएगा।

पहले चरण पूरा होने पर इसकी निर्माण लागत करीब छह हजार करोड़ रुपये होगी। एयरपोर्ट के विस्तार में एमआरओ के साथ एक रनवे बनेगा। यात्रियों की संख्या के साथ इसका विस्तार छह रनवे तक होगा। दस एयरो ब्रिज 25 पार्किंग स्टैंड होंगे।

कैट तीन एयरपोर्ट

देश में छह कैट तीन एयरपोर्ट के बाद सातवां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दृश्यता कम होने पर भी विमान इस एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग एवं उड़ान भर सकेंगे। 3900 मी लंबे और साठ मीटर चौड़े रनवे का सौ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

डिजिटल यात्रा और शून्य कार्बन उत्सर्जन एयरपोर्ट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida international airport) पर तकनीकी की भरपूर इस्तेमाल किया गया है। यात्रियों का डिजिटल यात्रा का अनुभव मिलेगा। एयरपोर्ट पूरी तरह से पेपरलैस होगा। यात्री डिजिटल टिकट के जरिये यात्रा कर सकेंगे। क्यूआर कोड स्कैन कर चेक इन की सुविधा होगी।

शून्य कार्बन उत्सर्जन एयरपोर्ट के लिए प्राकृतिक रोशनी, वायु, उपयोग हो चुके पानी को रिसाइकिल किया जाएगा। एयरपोर्ट परिसर में ई वाहन का ही संचालन होगा। एयरपोर्ट की पचास प्रतिशत बिजली खपत को वायु एवं सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। इसके लिए टाटा ग्रुप के साथ अनुबंध हो चुका है।

भारतीय संस्कृति की झलक

एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के डिजायन में भारतीय संस्कृति को केंद्र में रखा गया है। सीढ़ियां बनारस के घाट और छत गंगा नदी की लहरों से प्रेरित हैं। प्राचीन वास्तुकला में हवेलियों से प्रेरित प्रांगण और हवादार बनाने के लिए खिड़कियों को जालीदार बनाया गया है।

एयरपोर्ट में केवल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य ही शेरू है। सिविल कार्य के बाद आंतरिक साज सज्जा शुरू होगी। इसमें भी भारतीय संस्कृति की झलक होगी। एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों के लिए पांच सितारा होटल का निर्माण हो रहा है।

चालीस एकड़ में एमआरओ

विमानों के लिए की मेंटेनेंस के लिए चालीस एकड़ में एमआरओ विकसित किया जाएगा। इसके लिए विकासकर्ता कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जेवर को एमआरओ का बड़ा हब बनाने की योजना है। इसके लिए 1365 हे. जमीन अधिगृहीत की जा रही है। इसमें एयरबस, बोइंग जैसे विमानों की मेंटेनेंस, ओवरहालिंग की सुविधा होगी।

80 एकड़ में विकसित हो रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब

आईजीआई एयरपोर्ट (IGI Airport) दिल्ली को गाजियाबाद (ghaziabad) व दिल्ली (delhi news) से 51 प्रतिशत कार्गो मिलता है। उत्तर प्रदेश के दोनों औद्योगिक जिलों से कार्गो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से देश दुनिया के बाजार तक पहुंचेगा। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रानिक, कृषि उत्पाद, चिकित्सा उपकरण इसमें अहम योगदान करेंगे।

ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर पर रेल, सड़क कनेक्टिविटी

एयरपोर्ट में अंडरग्राउंड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर विकसित होगा। इसमें रेल, सड़क कनेक्टिविटी होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ इसे यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। इसका काम तकरीबन पूरा होने को है।

टर्मिनल बिल्डिंग से निकलकर यात्री सीधे जीटीसी से बस, नमो भारत रेल, हाई स्पीड रेल से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। दिल्ली हावड़ा व दिल्ली मुंबई रेल मार्ग (Delhi Mumbai Rail Marg) से जोड़ने के लिए चोला व रूंधी के बीच 61 किमी रेलवे लाइन के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है।

2050 तक सात करोड़ यात्री सालाना क्षमता

एयरपोर्ट चार चरण में पूरा होगा। पहले चरण में 1.2 करोड़ सालाना यात्री क्षमता के साथ इसकी शुरुआत होगी। तीन करोड़ यात्री क्षमता के साथ दूसरा चरण व पांच करोड़ यात्री क्षमता के साथ तीसरा चरण होगा।चारों चरण पूरा होने पर परियोजना की कुल लागत 29561 करोड़ हो जाएगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी कार्य निर्धारित टाइम लाइन से पूरे हो रहे हैं। पंद्रह दिसंबर से पहले कामर्शियल फ्लाइट ट्रायल पूरा होगा। अप्रैल से एयरपोर्ट पर नियमित उड़ान सेवा शुरू होगी।

शैलेंद्र भाटिया, नोडल अधिकारी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

अब स्कूल में ही बनाना होगा मिड डे मील, बाहर से मंगाने पर कार्रवाई; नोटिस जारी

गाजियाबाद में प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में ताजा पका हुआ खाना न परोसने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। 11 इंटर कॉलेजों में मिड डे मील नहीं बनाया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इन स्कूलों को नोटिस जारी कर 10 दिन में स्कूल में ही खाना बनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद। प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूलों में ताजा पका हुआ खाना न परोसने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाल ही में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई संयुक्त जांच में पता चला है कि 11 इंटर कालेजों में मिड डे मील नहीं बनाया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा ने इन स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए अगले 10 दिन में स्कूल में ही खाना बनाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनमें शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल भी शामिल हैं।

इसके अलावा मुरादनगर, लोनी और रजापुर विकास खंड के कुछ प्राथमिक स्कूलों में भी मिड डे मील बनाने एवं वितरण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने बताया कि जल्द ही निरीक्षण के बाद इसका पता लगाया जाएगा।

इन स्कूलों को जारी किया गया नोटिस

नानक चन्द्र इंटर कॉलेज, सोन्दा, मुरादनगर

किसान नेशनल इंटर कॉलेज मुरादनगर

श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज, निवाडी

महर्षि दयानन्द् इंटर कॉलेज, गोविन्दपुरी, मोदीनगर

आर्य कन्या इंटर कॉलेज, गोविन्दपुरी, मोदीनगर

मनोहरी विद्या मन्दिर हायर सैकेंडरी स्कूल, नवयुग मार्किट, गाजियाबाद

चमेली देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज सौन्दा, मुरादनगर

संजय गांधी इंटर कॉलेज, निवाडी

हंस इंटर कॉलेज, मुरादनगर

पीबीएस कन्या इंटर कॉलेज, मोदीनगर

जैनमति उजागर गर्ल्स हायर सैकेंडरी स्कूल कविनगर

मिड डे मील का विवरण

कुल स्कूलों की संख्या 514

लाभार्थी छात्रों की संख्या 92 हजार

प्राथमिक स्कूलों में प्रतिछात्र कनवर्जन शुल्क 5.45 रुपये निर्धारित है

जूनियर हाई स्कूलों में प्रतिछात्र कनवर्जन शुल्क 8.17 रुपये निर्धारित है

डिजिटल अरेस्ट कर महिला को धमकाया, फिर ठग लिए 10 लाख; साइबर ठगों से ऐसे बचें

साइबर अपराधियों ने गाजियाबाद की एक महिला को कोरियर में ड्रग्स रखकर कनाडा भेजने के आरोप में फंसाया और पूरी रात डिजिटल अरेस्ट कर 10 लाख रुपये ठग लिए। महिला को धमकाया गया और उसके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर कराए गए। साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे विस्तार से पढ़िए आखिर पूरा मामला क्या है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने कविनगर निवासी युवती को कोरियर में ड्रग्स रखकर कनाडा भेजने का आरोप लगाकर जांच के नाम पर धमकाया और पूरी रात डिजिटल अरेस्ट कर 10 लाख रुपये ठग लिए।

पीड़िता आरोपितों की धमकी से डर गई और अपने बैंक खाते से मोबाइल से धनराशि ट्रांसफर करने के बाद अगले दिन बैंक जाकर भी बताए गए खाते में धनराशि ट्रांसफर कर आई। खाते में धनराशि ट्रांसफर होते ही आरोपितों ने कॉल काट दी। इसके बाद पीड़िता को ठगी का एहसास हुआ। पीड़िता की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है।

महिला को आया था फोन

कविनगर एच ब्लाक निवासी गार्गी गुप्ता के पास शुक्रवार शाम करीब पौने चार बजे एक व्यक्ति ने स्वयं को डीटीडीसी कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए फोन किया और कहा कि उनके नाम से एक पैकेट मुंबई से कनाडा के लिए बुक किया गया था, जिसमें छह एसबीआई के क्रेडिट कार्ड, पांच किलो कपड़े और 200 ग्राम ड्रग्स पाई गई है।

उन्हें बताया गया कि कंपनी ने उनके खिलाफ मुंबई में केस दर्ज कराया है। इसके बाद उनसे स्काइप कॉल के जरिए मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के अधिकारी से बात कराई गई। पीड़िता को साइबर क्राइम अधिकारी बनकर फोन करने वाले युवक ने कहा कि उनका स्टेटमेंट लेना है, इसलिए कमरे में कोई नहीं होना चाहिए और न ही वह फोन काट सकती हैं।

महिला को ऐसे झांसे में लिया

पीड़िता को धमकाकर उनके बैंक खाते और आधार की जानकारी लेने के बाद बताया गया कि उनके 24 बैंक खाते तीन महीने में खुले हैं। यह सभी खाते मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित ड्रग तस्कर मोहम्मद इस्लाम मलिक से जुड़े हुए हैं। उन्हें बताया गया कि आगे की जांच डीसीपी करेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ ही देर में डीसीपी बनकर उनसे बात की और उनके बैंक खातो की जानकारी मांगी।

पीड़िता ने बताया कि उनके दो बैंक खाते हैं, जिनमें से एक खाते में करीब 10 लाख रुपये और दूसरे बैंक खाते में दो हजार रुपये हैं। आरोपितों ने उनसे दोनों खातों की जांच के लिए करीब साढ़े तीन

आओ एक और एक ग्यारह बनें-बटेंगे तो कटेंगे एक हैं तो सेफ़ हैं, पूरे भारत के परिपेक्ष में सकारात्मक सोचें

हम सभ भारतीय एक ही दिशा में एक एक कदम चलते हैं तो एक साथ 142 .8 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं विश्व को भारत की 142 .8 करोड़ जनसंख्या का बुद्धि कौछल, कार्यबल शुभ संकल्प दिखाने का समय आ गया है- जनसंख्या वृद्धि की सकारात्मक सोच

वैश्विक स्तरपर भारत में गूंज रहे नारों बाटेंगे तो काटेंगे, एक हैँ तो सेफ़ हैं का आगाज़ पूरी दुनियाँ के हर देश में हो रहा है, लोग अपने-अपनी सोच से इसका अर्थ निकाल रहे हैं। मैंने 3 दिसंबर 2024 को सुबह सोशल मीडिया में एक हमारे मुस्लिम भाई के विचार सुने तो उनकी बुद्धि का लोहा माना, उन्होंने कहा यह दोनों नारे हमारे पूरे भारत की जाति धर्म मतभेद दंगे फसाद भुलाकर एक होने के लिए है, ताकि हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विकसित देश व वैश्विक गुरु बना सके अगर हम आपस में ही जाति धर्म में उलझे रहे तो विज़न 2047 कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए यह दोनों नारे सटीक बैठ रहे हैं इसका अर्थ एक और एक ग्यारह से लगाएं, जाती धर्म समुदाय से जोड़कर ना देखे!! बस, मैं उनका अर्थ पारदर्शिता से समझ गया व इसपर आर्टिकल बनाने की तैयारी कर रिसर्च किया, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है (1) भारत-142.86 करोड़ (2) चीन-142.57 करोड़ (3) अमेरिका - 34.43 करोड़ (4) इंडोनेशिया-27.38 करोड़ (5) पाकिस्तान-23.14 करोड़ इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, 142.8 करोड़ जनसंख्या एक-एक कदम चलते हैं तो 142.8 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं तभी विश्व को जीत सकेंगे आओ एक और एक ग्यारह बने-बटेंगे तो कटेंगेएक है तो सेफ़ हैं, पूरे भारत के परिपेक्ष में सकारात्मक सोचें भारत के बड़े बुजुर्गों, बुद्धिजीवियों, कौशलता निपुण विद्वानों कुछल नेतृत्व धारक मनीषियों के विचारों का हमारे देश में अण्खुट खज़ाना है, हालांकि इनकी वैचारिक शक्ति का प्रयोग और क्रियान्वयन भी संस्कारों की जननी भारत माता के गोद में किया जाता है।परंतु वर्तमान समय में हमारे भारतवर्ष में जो एक विषय जोरों से चर्चा में है, उस पर बहुत गंभीरता से हर देशवासी को सकारात्मक सोचना होगा यह विषय है !142 करोड़ जनसंख्या के कार्यबल, बुद्धि कौशल और शुभ संकल्प का संपूर्ण क्षमता के साथ दोहन करना।

साथियों यह विषय अगर हर भारतीय नागरिक जिसमें राजनैतिक शासन-प्रशासन, पक्ष विपक्ष, सभके समझ में आ गया, व उसका क्रियान्वयन पूर्ण स्केल के साथ करना शुरू हुआ तो दुनियाँ की कोई ताकत भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ विकसित देश बनाने में नहीं रोक सकती साथियों बात अगर हम माननीय पीएम जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के दौरान भारतीय समुदाय से बातचीत की करें तो उन्होंने कहा था आज हिन्दुस्तान से 130 करोड़ लोग और मैं जापान में बैठे हुए लोगों की भी आंखों में वही देख रहा हूं 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास संकल्प, सपने और इस 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराटसामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा दोस्तों। हमारे सपनों काभारत हम देखके रहेंगे।आज भारत

अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति अपनी संस्थाओं के, अपने खोये हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है।

साथियों बात अगर हम कुछ अवधि से चर्चाओं में चल रहे विषय जाति आधारित जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून की करें तो हालांकि नीतिगत फैसला अभी नहीं हुआ है। परंतु अभी ज़रूरत है वर्तमान ज़नसंख्या स्थिति को संज्ञान में लेकर उसके कार्यबल, बौद्धिक कौशलता का उपयोग करने के रणनीतिक रोडमैप बनाने की, क्योंकि भारत माता की मिट्टी के गुण इतने प्रभावी हैं कि यहां हर नागरिक में किसी न किसी कौशलता बुद्धिमता का गुण समाया हुआ है! बस! ज़रूरत है उसे तराशने की, उचित ट्रेनिंग देने की, जिसमें अगर हम सफ़ल हो जाते हैं तो रोज़गार मांगने वाला रोज़गार सृजनकर्ता बन जाएगा।142.8 करोड़ लोगों के हाथों में काम होगा तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच क्या? 25 ट्रिलियन डॉलर तक की अर्थव्यवस्था भी ले जाने की क्षमता रखते हैं!

साथियों अगर हम वैश्विक रचना पर नजर घूमांए तो हमारा एक राज्य यूपी, दुनियाँ के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों के पांचवे देश के नम्बर में है, तो हम विचार करें कि, हमारे एक संयुक्त भारत में आज राज्य 35 हैं तो हमसे बहुत छोटी जनसंख्या वाले देशों के नागरिकों के हाथ में काम है, और कौछलता है तथा उनका जीवन स्तर उच्चतर है, तो फिर भारत में तो अपेक्षाकृत अधिक बुद्धि कौशलता और कार्य करने की क्षमता और काबिलियत है! हम तो उनसे कई गुना आगे बढ़ सकते हैं, बस जरूरत है उसे तराशने की जो काम राजनीतिक कौशलबुद्धि और वैचारिक एकता के मंत्र को अपनाने पर क्रियान्वयन होगा, यांने वैश्विक स्तरपर एक है तो सेफ है, बाटेंगे तो काटेंगे।

साथियों बात अगर हम 135 करोड़ साथियों के कार्यबल बुद्धि कौशलता के निखार की करें तो हालांकि अलग अलग मंत्रालयों के तहत कार्य योजनाएं चलाई जा रही है। व कौशलता विकास मंत्रालय भी बना हुआ है परंतु मेरा एक सुझाव है जिस तरह से सेनाओं के तीनों अंगों के लिए एक पीडीएफ पद का सृजन कर नियुक्ति की गई है ठीक उसी प्रकार 142.8 करोड़ जनसंख्या के लिए अलग-अलग मंत्रालयों के तहत कार्यबल बुद्धि कौशलता क्षमता का उपयोग करने बनाए गए अपने-अपने विभाग के रणनीतिक रोडमैप को एक सूत्रीय पद याने एक विशेष मंत्रालय बनाकर यानें तालमेल के लिए उस मंत्रालय का सृजन कर माननीय पीएम के अंतर्गत दिया जाए तो इस कार्य में तीव्रता से वृद्धि होगी और हमारी 142.8 करोड़ जनसंख्या की कार्यक्षमता और उनकी कौछल क्षमता के दोहन का अभूतपूर्व विकास होगा और हम शीघ्र ही लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और आत्मनिर्भर बहुत तेज़ी से बनेंगे।

साथियों बात अगर हम जातिगत, राजनीतिक स्थिति आंदोलनों, आरक्षण की लड़ाई की करें तो मेरा मानना है कि अगर 142.8 करोड़ पूरी जनसंख्या को उनके कार्यबल और कौछलता का आभास करा कर उनको निख़ारा जाएगा तो उनको यह एहसास कराकर सफ़लता की चाबी उनको दी गई, तो उपरोक्त सभी मामलों का अंत होने की भी संभावना है, क्योंकि हर हाथ में रोज़गार होगा तो जातीयता, आरक्षण, राजनीति, नकारात्मकता की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, हालांकि अगर हम इस मुद्दे को नकारात्मकता से संज्ञान में लेकर विश्लेषण करें तो नकारात्मक रिजल्ट ही निकलेगा इसीलिए हमें इस विषय को सकारात्मकता से संज्ञान में लेने की ज़रूरत है।

साथियों बात अगर हम कुछ कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा एक कार्यक्रम के संबोधन की करें तो पीआईबी के अनुसार उन्होंने भी 135 करोड़जनसंख्या के बारे में कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के उज्ज्वल भविष्य और विश्व में भारत को उन्नत स्थान दिलाने के लिए मन में आशा जगाने, संकल्प लेने और अपने कार्यों से इन आशाओं को पूरा करने का है। उन्होंने कहा कि भारत 135 करोड़ की आबादी वाला देश है और अगर सभी 135 करोड़ भारतीय आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक-एक संकल्प लें तो एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी।अगर हम सब भारतीय एक ही दिशा में एक एक कदम चलते हैं, तो हम सब एक साथ 135 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को प्रेरणा का एक स्रोत व चेतना जागृत करने का माध्यम बनाकर भारत के विकास का राजमार्ग बनाएं।

क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी)
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

अतः अगर हम उपरोक्त विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आओ एक और एक ग्यारह बने, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैँ तो सेफ़ हैं, पूरे भारत के परिपेक्ष में सकारात्मक सोचें।हम सब भारतीय एक ही दिशा में एक एक कदम चलते हैं तो हम सब एक साथ 142.8 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं, विश्व को भारत की 142.8करोड़ जनसंख्या का बुद्धि कौशलता, कार्यबल शुभ संकल्प दिखाने का समय आ गया है।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित

परिवहन विशेष न्यूज

मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी के तहत 2024 में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मंगलवार, 03 दिसम्बर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया।

यह सम्मान स्पार्क मिंडा फाउंडेशन के प्रयासों को दर्शाता है, जो मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसने 2015 में शुरू की गई अपनी पहल सक्षम के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की मदद की है। इस पहल ने 21,000 से अधिक विकलांग व्यक्तियों को उनकी गतिशीलता, शिक्षा, रोजगार और समग्र सशक्तिकरण आवश्यकताओं को संबोधित करके लाभान्वित किया है। आज तक, स्पार्क मिंडा समूह की फैक्ट्रियों में 1,200 से अधिक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

स्पार्क मिंडा फाउंडेशन ने दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण, सहायक उपकरण और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थायी केंद्र भी स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, फाउंडेशन अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में वार्षिक शिविर आयोजित करता है।

फाउंडेशन ने भारत भर में दिव्यांगों के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाने के लिए 35 से अधिक सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और संगठनों के साथ सहयोग किया है। अधिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम अंग, ऑर्थोटिक्स, वॉकर, बैसाखी और व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण भी वितरित किए जाते हैं।

इस अवसर पर स्पार्क मिंडा फाउंडेशन की अध्यक्ष सारिका मिंडा ने कहा कि यह पुरस्कार संगठन के समावेशिता के दृष्टिकोण तथा विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उसके सतत प्रयासों को दर्शाता है।

यह पुरस्कार समूह को पहले भी मिले पुरस्कारों में शामिल है, जिनमें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और सीआईआई-आईटीसी स्थिरता पुरस्कार शामिल हैं।

मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो ऑटोमोटिव घटकों और प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। स्पार्क मिंडा समूह के हिस्से के रूप में, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सुरक्षा प्रणालियों, ड्राइवर सूचना प्रणालियों और आंतरिक प्लास्टिक घटकों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। ये पेशकशें दोपहिया, चार पहिया और वाणिज्यिक वाहन खंडों में विविध ग्राहकों को पूरा करती हैं।

मजबूत विनिर्माण पदचिह्न के साथ, मिंडा कॉर्पोरेशन भारत भर में कई सुविधाएं संचालित करता है, जो स्थानीय उत्पादन और कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करता है। कंपनी अनुसंधान और विकास पर महत्वपूर्ण जोर देती है, जिसमें समर्पित केंद्र ऑटोमोटिव उद्योग की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं। मिंडा कॉर्पोरेशन ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सक्षम जैसी पहलों के माध्यम से स्थिरता और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में भी प्रगति की है। कंपनी समावेशन, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करती है।

टेरा चार्ज और एएआई ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भोपाल के पहले ईवी चार्जिंग हब का किया अनावरण

परिवहन विशेष न्यूज

टेरा चार्ज ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हब का उद्घाटन किया है। हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में स्थित यह सुविधा की शुरुआत शुक्रवार, 29 नवंबर 2024 को ही हो गई हैं। इस कार्यक्रम में टेरा चार्ज टीम के सदस्य और एएआई के प्रतिनिधि शामिल हुए।

चार्जिंग हब 75 वर्ग मीटर में फैला है और एक साथ चार ईवी को संभालने में सक्षम है। इसमें जापानी तकनीक पर आधारित एक स्लो चार्जर और एक 30 किलोवाट का फास्ट चार्जर है, जो सार्वजनिक और वाणिज्यिक बेड़े के वाहनों की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करता है। इस पहल का उद्देश्य भोपाल के ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना और क्षेत्र में ईवी मालिकों के लिए पहुँच में सुधार करना है।

उद्घाटन के अवसर पर टेरा चार्ज के बिजनेस डायरेक्टर अपूर्व दास महापात्रा ने एएआई के साथ सहयोग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में इसके महत्व के बारे में बात की। उन्होंने परियोजना का समर्थन करने के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी, एजीएम कमर्शियल केपीएस सिकरवार और मैनेजर कमर्शियल निधि श्रीवास्तव सहित एएआई अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। महापात्रा ने कहा कि संयुक्त पहल से भोपाल में ईवी मालिकों को लाभ मिलने और इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

टेरा चार्ज मोबाइल ऐप का उपयोग करके नए चार्जिंग हब का पता लगाया जा सकता है।

टेरा चार्ज भारत के ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए आगे की पहल और साझेदारी की भी खोज कर रहा है, जो देश के बढ़ते ईवी बाजार के साथ संरेखित है, जिसके 2024 के अंत तक 23.38 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

टेरा चार्ज भारत के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक उभरती हुई कंपनी है, जो देश के संधारणीय गतिशीलता में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय और सुलभ चार्जिंग समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी प्रमुख शहरी और अर्ध-शहरी स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित करने पर काम करती है, जिसका लक्ष्य निजी और वाणिज्यिक ईवी मालिकों की बढ़ती संख्या को पूरा करना है।

सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के साथ सहयोग करते हुए, टेरा चार्ज हवाई अड्डों, राजमार्गों और शहरी केंद्रों जैसे रणनीतिक स्थानों पर उन्नत चार्जिंग हब स्थापित करता है। कंपनी की चार्जिंग सुविधाओं में अक्सर अपने उपयोगकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेज़ और धीमे दोनों तरह के चार्जर शामिल होते हैं। टेरा चार्ज मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी सेवाओं में प्रौद्योगिकी को भी एकीकृत करता है, जिससे ईवी उपयोगकर्ता चार्जिंग पॉइंट का कुशलतापूर्वक पता लगा सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं।

टेरा चार्ज ईवी की सुलभता बढ़ाने और अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी निकायों और निजी संगठनों के साथ साझेदारी पर जोर देता है। भारत के ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में योगदान देकर, कंपनी कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ खुद को संरेखित करती है।

हुंडई मोटर ग्रुप ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के साथ रणनीतिक की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

दक्षिण कोरिया के हुंडई मोटर समूह ने बैटरी प्रौद्योगिकी और विद्युतीकरण में एक मजबूत अनुसंधान ढांचा स्थापित करने के लिए तीन प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और आईआईटी चेन्नई के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय बाजार की अनूठी आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार विकसित करना है।

एक बयान में कहा गया है कि इस सहयोग के मूल में आईआईटी दिल्ली के भीतर हुंडई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। हुंडई मोटर ग्रुप द्वारा प्रायोजित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य भारतीय बाजार की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैटरी और विद्युतीकरण समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईवी प्रौद्योगिकी में अग्रणी प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाना है।

हुंडई मोटर समूह के अनुसंधान एवं विकास योजना एवं समन्वय केंद्र के प्रमुख नक्सप सुंग ने कहा, ₹हमारा मानना है कि हुंडई सीओई भारत के शैक्षणिक परिदृश्य से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करेगा, जिससे नवाचार और भविष्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा।₹

हुंडई मोटर ग्रुप ने बैटरी तकनीक, सॉफ्टवेयर विकास, हाइड्रोजन ईंधन सेल और विद्युतीकरण में अनुसंधान गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पांच वर्षों यानी 2025 - 2029 में लगभग 7 मिलियन डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस सहयोग में आईआईटी दिल्ली में एक समर्पित ईवी अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी (CART) भी शामिल होगा।

हुंडई मोटर ग्रुप का मानना है कि आईआईटी के साथ साझेदारी से कोरियाई और भारतीय विशेषज्ञों के बीच अकादमिक-औद्योगिक शोध, प्रतिभा विकास और ज्ञान साझा करने में मदद मिलेगी। पहलों में तकनीकी आदान-प्रदान कार्यक्रम हुंडई के विशेषज्ञों द्वारा विशेष व्याख्यान और कोरिया में प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

यह पहल हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के सफल आईपीओ के बाद भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए हुंडई के चल रहे प्रयासों को भी दर्शाती है। हुंडई सीओई से उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने और भारत-विशिष्ट उत्पादों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

हुंडई मोटर इंडिया ने चेन्नई में बैटरी असेंबली प्लांट में निवेश किया है, जिसकी शुरुआती क्षमता अगले साल तक 75,000 बैटरी पैक प्रति वर्ष होगी। कंपनी ने ईवी बैटरी असेंबली के लिए अपने चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक हिस्सा मोबिस इंडिया लिमिटेड को पट्टे पर भी दिया है। बैटरी पैक के लिए आयात लागत कम करने में मदद के लिए ये बैटरियां हुंडई और उसकी सहयोगी कंपनी किआ को आपूर्ति की जाएंगी।

नवंबर में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बिक्री में इजाफा के साथ हुआ उलटफेर

परिवहन विशेष न्यूज

S. No.	TOP 500 SALES EV 3 WHEELER OEMs	BRAND	NOVEMBER
1	MAHINDRA LAST MILE MOBILITY LTD	MAHINDRA	9,505
2	BAJAJ AUTO	BAJAJ	6,122
3	YC ELECTRIC VEHICLE	YATRI	3,977
4	PIAGGIO VEHICLES	APE ELECTRIC	2,463
5	SAERA ELECTRIC AUTO PVT LTD	MAYURI	2,263
6	DILLI ELECTRIC AUTO PVT LTD	CITYLIFE	2,044
7	ENERGY ELECTRIC VEHICLES	UDAAN	1,232
8	MINI METRO EV L.L.P	MINI METRO	1,227
9	UNIQUE INTERNATIONAL	PANTHER	1,166
10	SAHNIANAND E VEHICLES PVT LTD	VANDE BHARAT	1,040
11	HOTAGE CORPORATION INDIA	BADSHAH	933
12	SKS TRADE INDIA PVT LTD	ARZOO	930
13	J. S. AUTO	JSA	911
14	CHAMPION POLY PLAST	SAARTHI	902
15	THUKRAL ELECTRIC BIKES PVT LTD	THUKRAL	873
16	TI CLEAN MOBILITY	MONTRA	703
17	KHALSA AGENCIES	KHALSA	686
18	ZENIAK INNOVATION INDIA LIMITED	INDO WAGEN	672
19	TERRA MOTORS INDIA PVT LTD	TERRA	671
20	ZEOPLUS AXIS INDIA PVT.LTD	ZEOFINE	627
21	VANI ELECTRIC VEHICLES PVT LTD	JEZZA	582
22	ATUL AUTO	ATUL	559
23	DAKSH INDUSTRIES	SARGAM	514

SOURCE: VAHAN

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के बाद वॉल्यूम में दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सेगमेंट है।

01. महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में बाजार की अग्रणी कंपनी बनी हुई हैं, जो यात्री और कार्गो डोमेन में कई मोबिलिटी ऑपरेशन को पूरा करती हैं। इस कंपनी ने नवंबर में 9,505 यूनिट की खुदरा बिक्री की है।

02. अब नंबर 02 पर बजाज ऑटो हैं, जो इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के बाजार में सिर्फ 17 महीने पुरानी कंपनी है। इस कंपनी ने नवंबर माह में 6,122 यूनिट की बिक्री की हैं।

03. वाईसी इलेक्ट्रिक, जो पहले लंबे समय से नंबर 02 नंबर पर विराजमान ई-थ्री-व्हीलर ओईएम थी। अगस्त से नंबर 3 पर आ गई है, जब से बजाज ऑटो ने इसे पीछे छोड़ दिया और ऐसा करना जारी रखा। नवंबर में वाईसी ने 3,977 यूनिट बेचीं।

04. नवंबर 2024 में इतालवी प्रमुख पियाजियो ने 2,463 की यूनिट बिक्री कर चौथे स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया हैं, जो पिछले अक्टूबर महीने से दो पायदान ऊपर हैं यानी पिछले महीने छठवें पायदान पर थी।

05. ई-रिक्शा और ई-कार्ट के मयूरी ब्रांड का निर्माण करने वाली सायरा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर उद्योग में जो पिछले माह चौथे स्थान पर थी। वह कंपनी एक पायदान फिसल कर पांचवें स्थान पर आ गई हैं। 2,263 यूनिट के साथ नवंबर में लगातार तीसरा महीना-दर-महीना गिरावट दर्ज की गई।

चार अंकों में अपनी बिक्री करने वाली पांचवें पायदान से छठवें पायदान पर दिल्ली इलेक्ट्रिक 2044 बिक्री कर नीचे आ गई हैं।

07. सातवें पायदान पर एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 1,232 यूनिट बिक्री कर एक पायदान ऊपर आ गई हैं। अक्टूबर माह मे यह कंपनी आठवें पायदान पर थी।

08. सातवें पायदान से खिसक कर आठवें पायदान पर मिनी मेट्रो ने 1,227 यूनिट्स बिक्री की हैं।

09. यूनिक इंटरनेशनल 1,166 यूनिट्स बिक्री कर अपने नवें पायदान पर और साहनीआनंद ई-व्हीकल्स 1,040 यूनिट्स बिक्री कर वाहन पोर्टल पर अपना वहीं यानी दसवें पायदान को बरकरार रखा हैं।

वाहन पोर्टल पर तीन अंकों मे अपनी यूनिट्स की बिक्री दर्ज करने वाली कंपनियों मे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला हैं।

11. हॉटेज कॉर्पोरेशन इंडिया जो अक्टूबर माह में तेरहवें स्थान पर था, अब 933 यूनिट्स की बिक्री कर ग्यारहवें स्थान पर आ गया हैं।

12. एसकेएस ट्रेड इंडिया 930 यूनिट्स बिक्री कर पिछले महीने के ग्यारहवें पायदान से नवंबर माह में बारहवें स्थान पर खिसक गई हैं।

13. जेएस ऑटो ने 911 यूनिट्स की बिक्री में बढ़ोतरी कर दो पायदान ऊपर चढ़ तेरहवें पायदान पर काबिज हैं। अक्टूबर महीने में पंद्रहवें पायदान पर विराजमान था।

14. पिछले महीने अक्टूबर में बारहवें पायदान से 902 यूनिट्स की बिक्री कर चौदहवें पायदान पर चैंपियन पॉलीप्लास्ट खिसक गई हैं। कुछ साल पहले की बात करें तो यह कंपनी नंबर एक और दो पर हुआ करती थी।

15. ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स अपनी यूनिट्स की बिक्री में बढ़ोतरी कर धीरे-धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। 873 की यूनिट्स की बिक्री कर पंद्रहवें पायदान पर आ गई हैं।

16. जबरदस्त उछाल के साथ बजाज ऑटो की वृद्धि के समान मुरुगप्पा समूह की कंपनी टीआई ग्रीन मोबिलिटी जिसका ब्रांड मोंट्रा इलेक्ट्रिक हैं। जिसने हाल ही में इस क्षेत्र में कदम रखा है, तेजी से रैंक पर ऊपर चढ़ रही है। जो पिछले महीने तेइसवें पायदान पर थी। चेन्नई स्थित कंपनी ने नवंबर में 703 इकाइयों की खुदरा बिक्री दर्ज की है। यह कंपनी साल की शुरुआत में काफी नीचे थी। यह अब तक का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन है।

17. खालसा ईवी 686 यूनिट्स के साथ सत्रहवें पायदान पर हैं। खालसा ईवी पिछले महीने चौदहवें पायदान पर थी।

18. जेनियक इनोवेशन 672 यूनिट्स के साथ अपनी पुरानी पोजीशन पर विराजमान हैं।

19. टेरा मोटर्स 671 यूनिट्स बिक्री कर पिछले माह के मुकाबले दो पायदान नीचे खिसक गया हैं।

20. जिओप्लस ऐक्सिस इंडिया 627 यूनिट्स की बिक्री कर एक पायदान ऊपर आ गया हैं।

21. वाणी इलेक्ट्रिक 582 यूनिट्स बिक्री कर दो पायदान नीचे खिसक गया हैं। पिछले महीने उन्नीसवें पायदान पर था।

22. अतुल ऑटो 559 यूनिट्स बिक्री कर अपनी पुरानी पोजीशन को बरकरार रखा हैं।

23. दक्ष इंडस्ट्रीज़ 514 यूनिट्स बिक्री कर एक पायदान ऊपर आ गया है। यह कंपनी पिछले महीने चौबीसवें पायदान पर थी।

जिन कंपनियों ने पिछले माह अक्टूबर में 500 यूनिट्स की बिक्री का आकड़ा पर किया था, जैसे की आलफाइन इंडस्ट्रीज़ ने 711 यूनिट्स, लेकिन नवंबर में मात्र 273 यूनिट्स, बेस्टवेज एजेन्सीस ने 536 यूनिट्स, नवंबर में 482 व श्री बरसाना ई-व्हीकल्स 514 यूनिट्स बिक्री की थी, नवंबर में 478 यूनिट्स की बिक्री पर सिमट गई।

पासाडेना में चल रहे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयासों के तहत नए ईवी चार्जिंग स्टेशनों का किया गया उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

पासाडेना के मेयर विक्टर गोर्डो और काउंसिल सदस्य जीन मसुदा ने सोमवार को सिटी मैनेजर मिगुएल मार्केज़ और पासाडेना वाटर एंड पावर के कार्यवाहक महाप्रबंधक डेविड रेयेस के साथ मिलकर 2575 पालोमा स्ट्रीट स्थित विक्ट्री पार्क में 23 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया।

ये चार्जर तीन नए लेवल 3 फास्ट चार्जिंग यूनिटों के साथ पासाडेना के वर्तमान सार्वजनिक ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करेंगे साथ ही ईवी मोटर चालकों की सेवा के लिए 21 लेवल 2 चार्जर भी लगाएंगे।

रेयेस ने कहा, ₹पासाडेना की नगर परिषद ने हमें कार्बन मुक्त ऊर्जा की ओर ले जाने के लिए एक बहुत ही आक्रामक नीति अपनाई है।" "वर्ष 2030 तक, जल और विद्युत विभाग शहर में बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से उस परिवर्तन में मदद करने के लिए बेहद प्रतिबद्ध है।"

रेयेस ने आगे कहा, "हमारे पास पूरे राज्य में सबसे मजबूत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग स्टेशन और सिस्टम में से एक है। इससे हमारे निवासियों के लिए संक्रमण आसान हो जाएगा, जिससे निवासियों और मेहमानों के लिए सार्वजनिक रूप से सुविधाजनक स्थान पर अपने वाहनों को चार्ज करना आसान हो जाएगा।"

मेयर गोर्डो ने इस विचार की ओर भी ध्यान दिलाया कि सैन गैब्रियल घाटी और उसके बाहर के अन्य शहरों को भी समान रूप से प्रतिबद्ध प्रयास करना चाहिए।

पासाडेना में चल रहे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयासों के तहत नए ईवी चार्जिंग स्टेशनों का किया गया उद्घाटन

उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि लोग पूरे शहर और उसके बाहर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए उत्सुक हैं और इसलिए पासाडेना को अपना काम करने पर गर्व है।" लेकिन इससे पहले कि हम उस बिंदु पर पहुँचें जहाँ हर किसी को इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक चार्जिंग का उपयोग करने का अवसर मिले, अन्य शहरों को भी यही करना होगा। पासाडेना एक द्वीप नहीं है। पासाडेना 88 शहरों वाले काउंटी में मौजूद है।

उन्होंने आगे कहा, "अकेले सैन गैब्रियल घाटी में 31 शहर हैं, जिनमें 2.1 मिलियन लोग रहते हैं और इसलिए हम उस बुनियादी ढांचे से बहुत पीछे हैं जो उस आबादी का समर्थन करने और लोगों के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी कार से बाहर निकलना संभव बनाने के लिए आवश्यक है।"

पीडब्ल्यूपी के प्रवक्ता ने कहा कि पासाडेना निवासी अपने वाहनों को चार्ज करने के लिए फ्लो ईवी ऐप का उपयोग करेंगे और उनसे "प्रतिस्पर्धी" दरें ली जाएंगी।

नए पीडब्ल्यूपी सार्वजनिक ईवी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में, रॉबिन्सन पार्क वर्तमान में अपने स्वयं के नए चार्जर्स का परीक्षण भी कर रहा है, जिसका आधिकारिक रिबन काटने का समारोह 2025 की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा।

पासाडेना के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पीडब्ल्यूपी के कार्यक्रमों और प्रोत्साहनों के बारे में अधिक जानकारी PWPweb.com/EV पर उपलब्ध है।

ऑटो कम्पोनेंट उद्योग की वृद्धि में मंदी का खतरा: क्रिसिल

परिवहन विशेष न्यूज

क्रिसिल के अनुसार भारत के ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में राजस्व वृद्धि में मंदी आने वाली है, वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वृद्धि दर केवल 6-8% है, जो पिछले वित्त वर्ष में देखी गई 14% वृद्धि से कम है। इस मंदी का कारण दोपहिया वाहनों को छोड़कर नए वाहनों की मांग में गिरावट, साथ ही वैश्विक व्यापक आर्थिक चुनौतियाँ, खासकर यूरोप और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में हैं।

निर्यात वृद्धि वित्त वर्ष 2024 में देखी गई 13% वृद्धि से कम रहने की उम्मीद है, लेकिन प्रतिस्थापन खंड में स्थिर मांग से समग्र वृद्धि को बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए परिचालन लाभप्रदता 12-13% पर स्थिर रहेगी, जिसे लागत में कमी के उपायों और बेहतर मूल्य निर्धारण से मदद मिलेगी।

इस क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से यात्री वाहन ओईएम की विस्तार योजनाओं से प्रेरित है, और निवेश को स्वस्थ नकदी प्रवाह द्वारा वित्तपोषित किए जाने की उम्मीद है। इससे बाहरी उधार पर निर्भरता कम होती है, जिससे क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर रहती है।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने बताया कि दोपहिया ओईएम में दोहरे अंकों की वृद्धि होगी, जबकि अन्य ओईएम खंडों में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है। हाल के वर्षों में वाहनों की मजबूत बिक्री के कारण प्रतिस्थापन राजस्व वृद्धि 8-9% पर बनी रहने की उम्मीद है।

निर्यात में कमी आई है, जो कुल सेक्टर राजस्व का लगभग 15% है, जो वित्त वर्ष 2022 में 17% से कम है। इसके बावजूद भारत में उच्च-मार्जिन वाले घटकों की बढ़ती हिस्सेदारी लाभप्रदता का समर्थन करना जारी रखती है। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी आ रही है, क्रिसिल ने ईवी घटकों में निवेश में वृद्धि की रिपोर्ट की है, ऑटोमोटिव निर्माताओं द्वारा वित्त वर्ष 25 और वित्त वर्ष 26 में 16,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 24 से 25% अधिक है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की बढ़ती मांग के साथ वैश्विक चुनौतियों के बावजूद यह क्षेत्र स्थिर वृद्धि के लिए तैयार है। क्रिसिल ने मजबूत ऋण सुरक्षा मीट्रिक का अनुमान लगाया है, जिसमें ब्याज कवरेज 8-9 गुना होने का अनुमान है, जो इस क्षेत्र की वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है।

भारतीय स्कूल डिजिटल साक्षरता और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं?

विजय गर्ग

भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक नवाचारों के साथ मिश्रित किया जा रहा है। एनईपी और आरटीई जैसी नीतियों ने समावेशिता, कौशल-निर्माण और भावनात्मक कल्याण पर जोर देते हुए सीखने को फिर से परिभाषित किया है। प्रगतिशील नीतियों और समग्र शिक्षा पर बढ़ते जोर के कारण भारतीय शिक्षा परिदृश्य में गहरा बदलाव आया है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने से लेकर परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने तक, इस क्षेत्र ने समावेशिता और नवाचार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज, शिक्षा न केवल अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करती है, बल्कि माता-पिता और स्कूलों के बीच साझेदारी को भी बढ़ावा देती है, जिससे छात्रों के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली तैयार होती है। इन परिवर्तनों को अपनाते हुए, स्कूलों ने मूल मूल्यों को संरक्षित करते हुए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली का सार जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने, छात्रों को अप्रत्याशित भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उपकरणों से लैस करने में निहित है। इसे पहचानते हुए, स्कूल उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा आकार की दुनिया के लिए कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में शुरुआती अनुभव छात्रों को उन चुनौतियों के लिए तैयार करता है जो उन्हें 10-15 वर्षों तक इंतजार कराती हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली आधुनिक नवाचारों के साथ परंपरा का मिश्रण करते हुए विकसित हो रही है। इन बदलावों को जानने के लिए इंडिया टुडे ने पुणे के संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ट्रस्टी प्रणीत मुंगाली से बात की. व्यस्त भविष्य के लिए नवाचार शिक्षण आधुनिक शिक्षा रटने से कहीं अधिक की मांग करती है; इसके लिए जुड़ाव, प्रासंगिकता और भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। स्कूलों ने अपनी शिक्षण पद्धतियों में सोशल इमोशनल लर्निंग (एसईएल) को शामिल करके इस चुनौती का सामना किया है। एसईएल इतिहास, विज्ञान और गणित जैसे विषयों में सहजता से घुलमिल जाता है, जिससे पाठ अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, छात्र अपनी प्रेरणाओं का पता लगाने के लिए ऐतिहासिक शख्सियतों की भूमिका निभा सकते हैं या समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साथियों के साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। समूह परियोजनाएं

सहयोग को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि छात्र भूमिकाएं आवंटित करना और साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करना सीखते हैं, जिससे टीम वर्क और सहानुभूति दोनों को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा के केंद्र में मूल्य ₹तेजी से तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभुत्व वाले युग में, स्कूल मूल्यों के महत्व पर जोर दे रहे हैं। व्यक्तिगत पूर्ति और भौतिक सफलता के बीच संतुलन बनाते हुए, पाठ्यक्रम को भावनात्मक रूप से लचीले व्यक्तियों का पोषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ढांचे के केंद्र में विवेक की अवधारणा है सही और गलत को पहचानने की क्षमता, "संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स, पुणे के ट्रस्टी, प्रणीत मुंगाली ने कहा। यह कालातीत कौशल दैनिक सीखने में बुना जाता है, जो छात्रों को नैतिक रूप से ईमानदार और भावनात्मक रूप से संतुलित वयस्क बनने के लिए मार्गदर्शन करता है। समसामयिक चुनौतियों का समाधान करना जैसे-जैसे शिक्षा परिदृश्य विकसित हो रहा है, स्कूल सक्रिय रूप से डिजिटल साक्षरता, पाठ्यक्रम अनुकूलनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा पर विशेषज्ञों द्वारा बार-बार आयोजित की जाने वाली कार्यशालाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि छात्र डिजिटल दुनिया को जिम्मेदारी से नेविगेट करने में सक्षम हों। इन-हाउस एआई कोच व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे बच्चों को प्रौद्योगिकी को जल्दी अपनाने में मदद मिलती है। ₹मानसिक स्वास्थ्य, छात्र कल्याण की आधारशिला है, जिसे संरचित एसईएल कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है। ये कार्यक्रम छात्रों को भावनाओं को प्रबंधित करने, सार्थक निर्माण करने के उपकरणों से लैस करते हैंरिश्ते, और सहानुभूति व्यक्त करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देकर, स्कूल खुश, अच्छी तरह से समायोजित व्यक्तियों की नींव रखते हैं जो किसी भी वातावरण में पनप सकते हैं,₹ उन्होंने आगे कहा। जैसे-जैसे भारत शिक्षा को फिर से परिभाषित करना जारी रखता है, ध्यान ऐसे शिक्षार्थियों की एक पीढ़ी तैयार करने पर रहता है जो जिज्ञासु, दयालु और सक्षम हों। परंपरा के साथ नवाचार को एकीकृत करके, स्कूल एक ऐसे भविष्य को आकार दे रहे हैं जहां छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से सफल होते हैं बल्कि समाज में सार्थक योगदान भी देते हैं। शिक्षा का परिवर्तन केवल परिवर्तन को अपनाने के बारे में नहीं है बल्कि इसे दृष्टि और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के बारे में है।

विद्यालय में विज्ञान पत्रिका का महत्व

विजय गर्ग

विज्ञान पत्रिकाएँ स्कूलों में छात्रों के सीखने के अनुभव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहां कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि वे क्यों महत्वपूर्ण हैं:

1. जिज्ञासा और रुचि को बढ़ावा देना:

* आकर्षक सामग्री: विज्ञान पत्रिकाओं में आकर्षक लेख, प्रयोग और चित्र होते हैं जो जिज्ञासा जगाते हैं और सीखने के लिए जुनून जगाते हैं।

* वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता: वे वैज्ञानिक अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से जोड़ते हैं, जिससे सीखना अधिक सार्थक और प्रासंगिक हो जाता है।

2. आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देना:

* जानकारी का विश्लेषण करना: छात्र वैज्ञानिक जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, पूर्वाग्रहों की पहचान करना और तथ्य और राय के बीच अंतर करना सीखते हैं।

* रचनात्मक सोच: विज्ञान पत्रिकाएँ अक्सर पहेलियाँ, प्रश्नोत्तरी और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती हैं जो छात्रों को नवीन समाधान खोजने के लिए चुनौती देती हैं।

3. पढ़ने और लिखने के कौशल में सुधार:

* उन्नत साक्षरता: विज्ञान लेख पढ़ने से शब्दावली, समझ और पढ़ने के प्रवाह में सुधार होता है।

* प्रभावी संचार: लेख लिखने या विज्ञान विषयों के बारे में चर्चा में भाग लेने से स्पष्ट और संक्षिप्त संचार कौशल विकसित होता है।

4. वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा देना:

*दुनिया को समझना: विज्ञान पत्रिकाएँ छात्रों को जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी सराहना विकसित करने में मदद करती हैं।

* सूचित निर्णय लेना: वैज्ञानिक प्रगति के बारे में सूचित रहकर, छात्र अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और भविष्य के करियर के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

5. भविष्य के वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों को प्रेरित करना:

* करियर अन्वेषण: वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ना छात्रों को एसटीईएम क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

* नवाचार को प्रोत्साहित करना: विज्ञान पत्रिकाएँ नवीनतम सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करती हैं, छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने और वैज्ञानिक प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित करती हैं।

निष्कर्षतः, विज्ञान पत्रिकाएँ स्कूलों के लिए अमूल्य संसाधन हैं। उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करके, शिक्षक एक अधिक आकर्षक और प्रभावी शिक्षण वातावरण बना सकते हैं जो विज्ञान के प्रति प्रेम को बढ़ावा देता है और छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक

कहानी : !! राजा और वृद्ध !

विजय गर्ग

ठण्ड का मौसम था. शीतलहर पूरे राज्य में बह रही थी. कड़ाके की ठण्ड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था.

महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है. पतली धोती और कुर्ता पहने वह वृद्ध ठण्ड से कांप रहा था. कड़ाके की ठण्ड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया.

उसके पास जाकर राजा ने पूछा, "क्या तुम्हें ठण्ड नहीं लग रही ?"

"लग रही है. पर क्या करूं ? मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं. इतने वर्षों से कड़कड़ाती ठण्ड मैं यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुज़ार रहा हूँ. भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठण्ड सह सकूं और उसमें जी सकूं." वृद्ध ने उत्तर दिया.

राजा को वृद्ध पर दया आ गई. उसने उससे कहा, "तुम यहीं रुको. मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ."

वृद्ध प्रसन्न हो गया. उसने राजा को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया.

वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया. किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया.

अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है. उसके मृत शरीर के पास ज़मीन पर एक संदेश लिखा हुआ है, जो वृद्ध ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था.

संदेश यह था : "इतने वर्षों से मैं पतली धोती-कुर्ता पहने ही कड़ाके की ठण्ड सहते हुए जी रहा था. किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली."

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों पर उठते सवाल

भारत मेंविज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को पारंपरिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण संसाधनों की कमी, पुराना पाठ्यक्रम और रटने और याद करने पर जोर के कारण व्यावहारिक शिक्षण अवसरों तक सीमित पहुंच शामिल है। भारत के पास चुनौतियों का अपना सेट है, उनमें से सबसे बड़ी भारतीय संस्थानों द्वारा कम फंडिंग है। भारत का अनुसंधान और विकास व्यय-जीडीपी अनुपात 0.7% के करीब है, जो विश्व औसत 1.8% से काफ़ी कम है। जबकि अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल व्यय (जीईआरडी) धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। युवा शोधकर्ताओं के फलने-फूलने के लिए एक सहायक वातावरण बनाने के लिए नीति निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों, फंडिंग एजेंसियों, वाणिज्यिक क्षेत्र और शैक्षणिक समुदाय के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

-प्रियंका सौरभ

भारतीय संस्थानों से एसटीईएम स्नातकों के एक बड़े प्रतिशत में आवश्यक कौशल का अभाव है, जो उद्योग और अनुसंधान प्रगति में बाधा डालता है। संस्थागत रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करने से कई शिक्षण-केंद्रित संस्थानों ने अक्सर निम्न-गुणवत्ता वाले आउटलेट में प्रकाशन पत्र और पेटेंट को प्राथमिकता दी है, कई संस्थानों में संकाय पर अत्यधिक बोझ है, पेशेवर विकास के लिए बहुत कम समय या प्रोत्साहन है। संकाय भर्ती अक्सर स्थानीयकृत होती है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन और दृष्टिकोण की विविधता सीमित हो जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी पहलों के लिए कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होती है, लेकिन सीमित योग्य कर्मियों और अपर्याप्त प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के कारण इन पहलों का उपयोग कम होने का ख़तरा है। वर्तमान संरचना संसाधनों, पाठ्यक्रम या संकाय के आदान-प्रदान की सुविधा नहीं देती है, जिससे शिक्षा और अनुसंधान के बीच विभाजन मज़बूत होता है, विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में योगदान के अपने समृद्ध इतिहास के साथ, भारत अब एक ऐसे महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ देश में (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश केवल एक चलन नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गया है।

प्रौद्योगिकी छात्रों और शिक्षकों के बीच सहयोग को सुगम बनाती है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और उपकरण परियोजनाओं पर वास्तविक समय में सहयोग को सक्षम करते हैं, टीमवर्क और संचार कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ये सहयोगात्मक अनुभव पेशेवर दुनिया में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की सहयोगात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण कई लाभ लाता है, यह चुनौतियों को भी सामने लाता है जिन्हें व्यापक परिवर्तन के लिए सम्बोधित करने की आवश्यकता है। डिजिटल डिवाइड एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुँच में असमानताएँ हैं। इस अंतर को पाटना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि सभी छात्रों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, प्रौद्योगिकी के उपयोग से लाभ उठाने के समान अवसर मिलें। शिक्षकों को भी अपने शिक्षण विधियों में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि वे प्रौद्योगिकी के उपयोग को समझने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग, जिसमें डेटा गोपनीयता और सुरक्षा शामिल है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना और शिक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों के विकास में नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण क़दम हैं।

शिक्षण-केंद्रित संस्थानों के मूल्यांकन को अनुसंधान मेट्रिक्स से अलग करके, रैंकिंग अनुसंधान आउटपुट पर शिक्षण गुणवत्ता को प्रतिबिंबित कर सकती है, जिससे इन संस्थानों पर निम्न-गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने का दबाव कम हो सकता है। शिक्षण संस्थानों को मूलभूत कौशल को मज़बूत करने के लिए, विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में, अनुसंधान पर शिक्षाशास्त्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक समर्पित ₹शिक्षण ट्रैक₹ शुरू किया जा सकता है, जिससे शिक्षाशास्त्र में रुचि रखने वाले संकाय सदस्यों को अकेले अनुसंधान आउटपुट के बजाय अपने शिक्षण कौशल के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। अनुसंधान संस्थान संयुक्त डिग्री कार्यक्रम बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी कर सकते हैं, जिससे उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अपना काम पूरा करने में मदद मिलेगी अनुसंधान-केंद्रित संस्थानों में अध्ययन। इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण एनआईटी सूरत और आईआईटी बॉम्बे के बीच सहयोग है, जो छात्रों को एक प्रमुख संस्थान में उन्नत अध्ययन पूरा करने की अनुमति देता है। सरकारी फंडिंग को शिक्षण संस्थानों के भीतर शिक्षाशास्त्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। ये केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और एसटीईएम शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे बड़े अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के बिना प्रणालीगत सुधार होंगे।

भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियाँ एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती हैं जिसमें पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण, अनुसंधान वित्त पोषण, संकाय विकास और विविधता पहल शामिल हैं। सरकार और उद्योग के सहयोग में वृद्धि से समर्थित नीतिगत सुधार, अधिक गतिशील, उद्योग-संरेखित और समावेशी एसटीईएम पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शिक्षा तक असमान पहुँच, पुराना पाठ्यक्रम और अपर्याप्त धन शामिल है। हालाँकि, इन चुनौतियों के बावजूद, देश में अच्छी तरह से सम्मानित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार ने शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। शिक्षा में निरंतर निवेश के साथ, भारत में सीखने और ज्ञान का एक अग्रणी केंद्र बनने और अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता है।

विज्ञान पत्रकारिता : विजय गर्ग

विज्ञान पत्रकारिता जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान और आम जनता के बीच की दूरी को पाटती है। इसमें जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में अनुवाद करना शामिल है, जिससे उन्हें व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया जा सके।

विज्ञान पत्रकारों की प्रमुख भूमिकाएँ:

* व्याख्या: वे जटिल वैज्ञानिक निष्कर्षों को सुपाच्य जानकारी में तोड़ते हैं, समाज के लिए उनके निहितार्थ और महत्व को समझाते हैं।

* तथ्य-जाँच: विज्ञान पत्रकार विश्वसनीय स्रोतों और सहकर्मी-समीक्षा अनुसंधान के साथ दावों की पुष्टि करके जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करते हैं।

* प्रासंगिकता: वे वैज्ञानिक खोजों के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं, उन्हें वर्तमान घटनाओं, ऐतिहासिक विकास और सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं।

* सार्वजनिक जुड़ाव: विज्ञान पत्रकार आकर्षक कहानियाँ बनाकर और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा को बढ़ावा देकर विज्ञान में सार्वजनिक रुचि को बढ़ावा देते हैं।

विज्ञान पत्रकारिता में चुनौतियाँ:

* विज्ञान की जटिलता: वैज्ञानिक अनुसंधान अत्यधिक तकनीकी और विशिष्ट हो सकता है, जिसके लिए पत्रकारों को वैज्ञानिक अवधारणाओं की मजबूत समझ की आवश्यकता होती है।

* समय की कमी: समाचार चक्र अक्सर त्वरित बदलाव के समय की मांग करते हैं, जिससे गहन शोध और विश्लेषण के लिए बहुत कम जगह बचती है।

* ग़लत सूचना और पूर्वाग्रह: ग़लत सूचना के प्रसार से निपटना और रिपोर्टिंग में निष्पक्षता सुनिश्चित करना विज्ञान पत्रकारिता में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।

विज्ञान पत्रकारिता का महत्व:

* सूचित जनता: विज्ञान पत्रकारिता जनता को जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने का अधिकार देती है।

* जवाबदेही: यह वैज्ञानिकों और संस्थानों को उनके शोध के लिए जवाबदेह बनाता है और वैज्ञानिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

* वैज्ञानिक साक्षरता: वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा देकर, विज्ञान पत्रकारिता अधिक सूचित और संलग्न नागरिक वर्ग में योगदान करती है।

विज्ञान पत्रकार कैसे बनें:

* शिक्षा: विज्ञान में एक मजबूत नींव, अधिमानतः विज्ञान क्षेत्र में डिग्री के साथ, आवश्यक है।

* पत्रकारिता कौशल: पत्रकारिता पाठ्यक्रम या इंटर्नशिप के माध्यम से मजबूत लेखन, रिपोर्टिंग और संपादन कौशल विकसित करें।

* नेटवर्किंग: अंतर्दृष्टि और अवसर प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य विज्ञान पत्रकारों के साथ संबंध बनाएं।

* विशेषज्ञता: उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए किसी विशिष्ट वैज्ञानिक क्षेत्र में विशेषज्ञता पर विचार करें।

प्रमुख विज्ञान पत्रकारों और आउटलेट्स के उदाहरण:

* कार्ल सागन: प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक।

* नील डेग्रसे टायसन: लोकप्रिय खगोल वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक।

* साइंटिफिक अमेरिकन: एक प्रमुख विज्ञान पत्रिका।

* प्रकृति: एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका।

* विज्ञान समाचार: एक साप्ताहिक विज्ञान समाचार पत्रिका।

निष्कर्ष

विज्ञान पत्रकारिता जनता को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में सूचित करने और संलग्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जटिल अवधारणाओं को तोड़कर, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर और विज्ञान में सार्वजनिक रुचि को बढ़ावा देकर, विज्ञान पत्रकार अधिक सूचित और वैज्ञानिक रूप से साक्षर समाज में योगदान करते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

हैल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त रखें ध्यान, ये गलतियां करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम

परिवहन विशेष न्यूज

हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको पुरानी बीमारियों का खुलासा करना जरूरी है। ऐसा न करने की स्थिति बीमा कंपनी आपका क्लेम खारिज कर सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू न करवाने और अधूरी जानकारी देने पर भी क्लेम खारिज हो सकता है। अगर आप वेटिंग पीरियड पूरा होने से पहले इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तब भी वह रिजेक्ट हो सकता है।

नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। साथ ही, बढ़ती उम्र के साथ भी कई बीमारियां भी शरीर को घर बना लेती हैं। ऐसे में बहुत-से लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज में ही खर्च हो जाता है। इस मुसीबत से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का सहारा लेना काफी अच्छा विकल्प रहता है। लेकिन, अगर आप कुछ जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी क्यों है?

कई बीमारियों के इलाज में काफी रकम खर्च होती है। हेल्थ इंश्योरेंस उसकी भरपाई करके आपको वित्तीय परेशानी से बचा सकता है। इससे आप मानसिक तनाव जैसी दिक्कतों से भी बच सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास चिकित्सा खर्च के लिए जरूरी रकम है। इससे आपको वित्तीय आजादी भी मिलती है। आप अपनी बचत को दूसरे जरूरी कामों में खर्च कर सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन की वजह

क्लेम के साथ जरूरी दस्तावेज नहीं जमा करते हैं या उसमें कोई गलती है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, तो उस क्लेम को भी बीमा कंपनियां अप्रूव नहीं करती हैं।

इंश्योरेंस क्लेम को सबमिट करने की एक समयसीमा होती है, इसमें देरी करने पर भी दिक्कत होती है।

अगर क्लेम नॉन-मेडिकल से जुड़ा है, जैसे कि दुर्घटना या आत्महत्या का प्रयास, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

अगर इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसी की शर्तों के अनुसार नहीं है, तो भी कंपनी उसे रिजेक्ट कर सकती है।

पॉलिसी लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

पॉलिसी में क्या कवर है और क्या नहीं, इसकी जानकारी लें।

पहले से कोई बीमारी है, तो उसका भी खुलासा करें।

क्लेम करते समय सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करें।

क्लेम जमा करने की समय सीमा का पालन करें।

पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले रिन्यू करें।

अगर कोई उलझन है, तो बीमा एजेंट से जानकारी लें।

क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्या करें?

इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा के मुताबिक, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद 60 महीने लगातार प्रीमियम चुकाया है तो बीमा कंपनी आपका क्लेम खारिज नहीं कर सकती, जब तक कि धोखाधड़ी साबित न हो जाए। अगर अधूरी जानकारी के कारण क्लेम खारिज हुआ है, तो उसे सुधार कर दोबारा सबमिट करें। आपकी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई, तो बीमा कंपनी से संपर्क करें। अगर कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप बीमा नियामक इरडा के पास शिकायत कर सकते हैं।

एलन मस्क को बड़ा झटका : अब नहीं मिलेगा मनचाहा सैलरी पैकेज, अमेरिकी अदालत ने लगाई रोक

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिका की एक अदालत ने दिग्गज कारोबारी एलन मस्क को बड़ा झटका दिया है। उसने मस्क की कंपनी टेस्ला की तरफ से उन्हें 55 अरब डॉलर के वेतन पैकेज वाली मांग को खारिज कर दिया है। डेलावेयर कोर्ट की चांसलर कैथलीन मैक्कॉर्मिक ने अपने फैसले में कहा कि टेस्ला के शेयरहोल्डर वोट के बावजूद वह अपना जनवरी का निर्णय नहीं बदलेंगी।

नई दिल्ली। अमेरिकी अरबपति और ऑटोमेकर टेस्ला के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने मस्क के 55.8 अरब डॉलर के सैलरी पैकेज को खारिज करने का अपना फैसला बरकरार रखा है।

डेलावेयर कोर्ट में जज Kathaleen McCormick ने टेस्ला के शेयरधारकों के जून वाले फैसले को भी नामंजूर कर दिया, जिसमें एलन मस्क का पैकेज बढ़ाने के लिए वोटिंग की गई थी। अदालत ने पाया कि टेस्ला ने दस्तावेंजों में 'भ्रामक जानकारी' दी थी। जज ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मस्क का प्रस्तावित वेतन काफी अधिक है और यह शेयरहोल्डर्स के हित में नहीं है।

अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा?

अदालत ने इस साल जनवरी में एलन मस्क के प्रस्तावित वेतन को खारिज कर दिया था। अब अदालत ने अपने उस फैसले को बदलने से इनकार किया है।

जज मैक्कॉर्मिक ने फैसले में कहा, 'टेस्ला ने एलन मस्क को सैलरी पैकेज देने के के लिए शेयरहोल्डर्स को जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनमें खामियां हैं। टेस्ला के वकीलों ने अपनी दलीलों में काफी रचनात्मकता दिखाई है, लेकिन उनके सिद्धांत स्थापित कानूनों के खिलाफ हैं। ऐसे में संशोधन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है।'

एलन मस्क की क्या प्रतिक्रिया है?

एलन मस्क ने अदालत के फैसले पर निराशा जताई है। उनका कहना है कि वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'किसी कंपनी के फैसले को शेयरधारकों के वोटों से नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि जजों द्वारा।'

इस मामले पर टेस्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसने एक्स पर लिखा, 'डेलावेयर के एक जज न्यायाधीश ने टेस्ला का मालिकाना हक रखने वाले शेयरधारकों के बहुमत को खारिज कर दिया है, जिन्होंने दो बार एलन मस्क को वह रकम भुगतान करने के लिए वोट दिया, जिसके वह हकदार हैं।'

टेस्ला का कहना है कि अदालत का फैसला गलत है और हम इसके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। उसने कहा कि अगर इस फैसले को पलटा नहीं जाता है, तो इसका मतलब होगा कि कंपनियों को उनके असल मालिक के बजाय जज चलाते हैं।

क्या है सैलरी पैकेज का पूरा मामला?

दरअसल, मस्क को 2018 में 55.8 अरब डॉलर का कंपनसेशन पैकेज दिया गया। टेस्ला का कहना था कि एलन मस्क ने कंपनी को बढ़ाने सबसे अहम भूमिका निभाई है और वह इस पैकेज के हकदार हैं। लेकिन, टेस्ला के शेयरधारक रिचर्ड टॉरनेटा ने मुकदमा दायर कर दावा किया कि इस पैकेज को खुद मस्क ने तय किया है, जिसे बोर्ड ने मंजूर भी कर लिया।

टॉरनेटा ने मस्क पर ₹ अनुचित लाभ₹ लेने का आरोप लगाया और अदालत से वेतन पैकेज को रद्द करने की मांग की। मस्क ने 2022 के ट्रायल में अपना बचाव करते हुए कहा कि टेस्ला के निवेशक दुनिया के सबसे समझदार हैं और वे उनके नेतृत्व क्षमता पर भरोसा करते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि टेस्ला ने केवल मॉडल 3 की सफलता के कारण ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है।

अस्थिरता से निपटना: निवेश में वैरिएंस क्यों मायने रखती है

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले कुछ वर्षों में मिड और स्मॉल कैप स्पेस ने काफी तेजी दिखाई है और वैल्यूएशन को बढ़ाया है। दिलचस्प बात यह है कि निवेशक अपनी लागत को औसत करने के उद्देश्य से मौजूदा सुधारों में भी अधिक खरीदारी कर रहे हैं। नतीजतन निवेश की बुनियादी बातें काफी हद तक कमजोर हो गई हैं और जोखिम से रिवॉर्ड का अनुपात कम हो रहा है।

नई दिल्ली। बाजार में उतार-चढ़ाव और अस्थिरता इक्विटी बाजार के इन-बिल्ट तत्व हैं, जिनसे कोई दूर नहीं रह सकता। हालांकि, अक्सर, ऐसे कारक अधिकांश निवेशकों की रातों की नींद हराम कर देते हैं और उन्हें निवेश का खराब अनुभव होता है।

ऐसी कई निवेश रणनीतियां हैं, जिन्हें अपनाने पर निवेशकों को मुश्किल दौर से सफलतापूर्वक निपटने में आसानी हो सकती है। हालांकि, निवेशक अक्सर मिड और स्मॉल कैप स्पेस के प्रति आत्मीयता पूर्वाग्रह विकसित कर लेते हैं और मानते हैं कि उतार-चढ़ाव भरी स्थितियों से लाभ उठाने के लिए कॉस्ट एवरेजिंग ही एकमात्र रणनीति है। यह हर समय सही निवेश दृष्टिकोण नहीं हो सकता है क्योंकि 6 फीट लंबा आदमी भी 5 फीट की औसत गहराई वाली नदी में डूब सकता है। औसत स्तर नदी की गहराई के अंतर को नहीं दर्शाता है जो कई जगहों पर औसत से कहीं अधिक गहरी हो सकती है।

यह एनालॉजी इक्विटी निवेश में भी बिल्कुल फिट बैठता है। पिछले कुछ वर्षों में, मिड और स्मॉल कैप स्पेस ने काफी तेजी दिखाई है और वैल्यूएशन को बढ़ाया है। दिलचस्प बात यह है कि निवेशक अपनी लागत को औसत करने के उद्देश्य से मौजूदा सुधारों में भी अधिक खरीदारी कर रहे हैं। नतीजतन, निवेश की बुनियादी बातें काफी हद तक कमजोर हो गई हैं और जोखिम से रिवॉर्ड का अनुपात कम हो रहा है।

यहीं पर वैरिएंस कारक महत्व प्राप्त करता है जो वास्तव में औसत से डेविएशन को मापता है। एक बड़ा डेविएशन औसत से आगे के फैलाव को दर्शाता है - जिससे औसत करना एक विवेकपूर्ण निवेश रणनीति नहीं है। निवेशक, जो इस मोड़ पर विकास चाहते हैं, उन्हें ऐसे स्टॉक की तलाश करनी चाहिए जो अभी भी उचित मूल्य पर हैं और जिनमें बढ़ने की गुंजाइश है। वर्तमान मूल्यांकन सस्ते नहीं हैं, लेकिन निवेशकों को अधिक उचित मूल्य निर्धारण के कारण मिड- और स्मॉल-कैप की तुलना में लार्ज-कैप स्टॉक को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसी के अनुरूप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एक नया फंड ऑफर (एनएफओ) लेकर आया है - आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड, जो 18 नवंबर से 2 दिसंबर, 2024 तक निवेशक के लिए खुला है। यह योजना कम बाजार अस्थिरता के साथ लॉन्गटर्म कैपिटल ग्रोथ और इक्विटी एक्सपोजर की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो अच्छे कॉर्पोरेट गर्वनेंस और उच्च नकदी प्रवाह वाली लार्ज-कैप कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

इस योजना में, कम अस्थिरता वाले शेयरों को उच्च भार के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है, जबकि उच्च-अस्थिरता वाले शेयरों को कम वेटेज दिया जाता है। एक गहन विश्लेषण सूचित स्टॉक चयन सुनिश्चित करता है, जिसमें बाजार की स्थितियों द्वारा गाइडेड पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स होता है। इसका उद्देश्य कम अस्थिरता के साथ लॉन्गटर्म ग्रोथ प्रदान करने वाला एक विविध पोर्टफोलियो बनाना है, जिसे बदलते बाजारों के अनुकूल बनाने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

बाजार की अनिश्चितता से मुकाबला : कम-अस्थिरता वाले पोर्टफोलियो राहत देने में सक्षम

बाजार से प्रेरित चिंता के बिना लॉन्गटर्म वेल्थ क्रिएशन की चाहत रखने वाले निवेशक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एनएफओ में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड है। 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक निवेश के लिए खुला एनएफओ अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और हाई कैश फ्लो वाली लार्ज-कैप कंपनियों पर केंद्रित है। आइए जानते हैं इस एनएफओ में क्या खास है।

नई दिल्ली। जबकि भारत का लॉन्गटर्म आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, अच्छे खासे मूल्य वाले इक्विटी बाजारों में तनाव के संकेत दिखने लगे हैं। अक्टूबर से, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि एसएंडपी मिडकैप और स्मॉल कैप सूचकांक क्रमशः 7 प्रतिशत और 4 प्रतिशत नीचे हैं।

वैश्विक और घरेलू कारक अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति में ढील दी है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इसका पालन नहीं किया है, बढ़ती खाद्य कीमतों से प्रेरित मुद्रास्फीति अपने लक्ष्य से ऊपर वापस आ गई है। इससे अपेक्षित दर कटौती में देरी हो सकती है, जिससे घरेलू विकास पर और दबाव पड़ सकता है। भू-राजनीतिक तनाव ने भी निवेशकों के

विश्वास को हिला दिया है, विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर से 12.5 बिलियन डॉलर से अधिक की निकासी की है।

निवेशकों के लिए, यह सुधार अस्थिर रहा है, खासकर वर्षों के मजबूत इक्विटी बाजार प्रदर्शन के बाद, ये महसूस किया जा रहा है। लंबी अवधि में दृष्टिकोण बनाए रखना और बाजार में उतार-चढ़ाव को सहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कम-अस्थिरता वाली इक्विटी रणनीति एक समाधान प्रदान करती है, जो निवेशकों को जोखिम का प्रबंधन करते हुए बाजार में बने रहने में मदद करती है।

बेहतर प्रशासन, उच्च पूंजी तरलता और उचित मूल्यांकन के लिए जाने जाने वाले लार्ज-कैप स्टॉक, मिड या स्मॉल कैप की तुलना में अस्थिरता के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। हाल ही में एफआईआई की बिक्री का खामियाजा लार्ज कैप को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए वे उलटफेर देख सकते हैं, जिससे लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

इसके अलावा, निवेशक लार्ज-कैप यूनिवर्स के भीतर सबसे कम अस्थिर स्टॉक की पहचान करने के लिए अस्थिरता फिल्टर लागू करके लाभ उठा सकते हैं, और इसे कम जोखिम के लिए अपने पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने के लिए सक्रिय प्रबंधन और फंडामेंटल रिसर्च के साथ जोड़ सकते हैं।

निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआई), जो निफ्टी 100 में सबसे कम अस्थिर स्टॉक को ट्रैक करता है, ने पिछले 20 वर्षों में से 12 में निफ्टी 100 टीआरआई से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसने यूरोजोन उथल-पुथल, कोविड-19 के दौर के बाद और उच्च मूल्यांकन की अवधि जैसे संकटों के दौरान गिरावट को सीमित करते हुए अधिकांश बाजार की बढ़त को पकड़ लिया है।

बाजार से प्रेरित चिंता के बिना लॉन्गटर्म वेल्थ क्रिएशन की चाहत रखने वाले निवेशक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की नवीनतम पेशकश (एनएफओ) में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड है। 18 नवंबर से 2 दिसंबर, 2024 तक निवेश के लिए खुला एनएफओ अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और हाई कैश फ्लो वाली लार्ज-कैप कंपनियों पर केंद्रित है।

इस योजना में, कम अस्थिरता वाले शेयरों को हाई-वेटेज के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है, जबकि उच्च-अस्थिरता वाले शेयरों को कम वेटेज मिलता है। इसका उद्देश्य कम अस्थिरता के साथ लॉन्गटर्म ग्रोथ प्रदान करने वाला एक विविध पोर्टफोलियो बनाना है, जिसे बदलते बाजारों के अनुकूल बनाने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

लो-वैरिएंस वाले पोर्टफोलियो: लॉन्गटर्म ग्रोथ के लिए एक सुरक्षित माध्यम

परिवहन विशेष न्यूज

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड (18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक निवेश के लिए खुला) कम अस्थिरता के साथ इक्विटी एक्सपोजर प्रदान करता है। मजबूत गर्वनेंस और नकदी प्रवाह वाले लार्ज-कैप स्टॉक पर केंद्रित इसका लक्ष्य विविध कम-अस्थिरता रणनीतियों के माध्यम से लॉन्गटर्म कैपिटल ग्रोथ है। आइए जानते हैं कि यह एनएफओ आपको किस तरह से फायदा पहुंचाएगा।

लार्ज-कैप कंपनियों को आमतौर पर स्थिर आय और तरलता के कारण कम अस्थिरता का अनुभव होता है। अक्टूबर 2024 तक, निफ्टी 100 टीआरआई वैल्यूएशन (पी/ई : 23.1, पी/बी : 3.66) निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई (पी/ई : 43, पी/बी : 5.44) और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई (पी/ई : 32.4, पी/बी : 4.25) से कम है। लो-वैरिएंस रणनीतियों में सक्रिय प्रबंधन को जोड़ने से परिणाम बेहतर हो सकते हैं। ब्याज दरें, यूएसडी डायनेमिक्स और तेल की कीमतें जैसे कारक, मैक्रो संकेतकों के साथ, पैसिव नियम-आधारित तरीकों से परे अवसरों की पहचान करने में मदद करते हैं। निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 टीआरआई ने 2005 से सीवाईटीडी 2024 तक 60 प्रतिशत वर्षों में निफ्टी 100 टीआरआई से बेहतर प्रदर्शन किया है।

नई दिल्ली। पिछले साल एक मजबूत बुल रन के बाद, इक्विटी बाजार करेक्शन मोड में प्रवेश कर गए हैं, जिसमें एफआईआई आक्रामक रूप से बिकवाली कर रहे हैं। बढ़ती अस्थिरता ने निवेश रिटर्न को प्रभावित किया है। ऐसे में एक लो-वैरिएंस वाला पोर्टफोलियो, जहां रिटर्न अपेक्षित औसत से बहुत अधिक अलग नहीं होता है, लॉन्गटर्म लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

जबकि औसत रिटर्न, जैसे कि 10 वर्षों में 12 प्रतिशत, आकर्षक हैं, किसी की वास्तविक वित्तीय यात्रा में अक्सर महत्वपूर्ण डेविएशन शामिल होते हैं। यह वैरिएंस पोर्टफोलियो अस्थिरता को उजागर करती है, यह विशेष रूप से वर्तमान समय में झलकता है - कोविड के बाद के दौर में - जोखिम लेने और निवेशकों के उत्साह के कारण निवेश रूझानों में बदलाव आया है।

अस्थिरता को बढ़ाने वाले जोखिम कारक

1. निवेशक व्यवहार: निवेशक, जो पहले डेट और गोल्ड के साथ इक्विटी को संतुलित करते थे, अब इक्विटी, विशेष रूप से मिड और स्मॉल कैप को प्राथमिकता देते हैं, जिससे जोखिम-रिवॉर्ड में अंतर होता है। मिड, स्माल और सेक्टोरल फंड्स जैसी जोखिम भरी कैटेगरीज में निवेश सीवाईटीडी 2024 (30 सितंबर तक) में 1.61 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया।

2. मूल्यांकन और ग्रोथ: मार्केट कैप-टू-जीडीपी 147 प्रतिशत (ऐतिहासिक औसत: 94 प्रतिशत) पर है, जो महंगे मूल्यांकन का संकेत देता है। बीएसई 500 कंपनियों के लिए राजस्व और आय वृद्धि पिछली तिमाहियों में तेजी से घटी है।

3. जियोपॉलिटिकल तनाव: लगातार यूएस-चीन ट्रेड वॉर और अन्य वैश्विक मुद्दे जोखिम को बढ़ाते हैं।

लो-वैरिएंस वाले पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का लाभ

लार्ज-कैप कंपनियों को आमतौर पर स्थिर आय और तरलता के कारण कम अस्थिरता का अनुभव होता है। अक्टूबर 2024 तक, निफ्टी 100 टीआरआई वैल्यूएशन (पी/ई: 23.1, पी/बी: 3.66) निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई (पी/ई: 43, पी/बी: 5.44) और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई (पी/ई: 32.4, पी/बी: 4.25) से कम है।

लो-वैरिएंस रणनीतियों में सक्रिय प्रबंधन को जोड़ने से परिणाम बेहतर हो सकते हैं। ब्याज दरें, यूएसडी डायनेमिक्स और तेल की कीमतें जैसे कारक, मैक्रो संकेतकों के साथ, पैसिव नियम-आधारित तरीकों से परे अवसरों की पहचान करने में मदद करते हैं। निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 टीआरआई ने 2005 से सीवाईटीडी 2024 तक 60 प्रतिशत वर्षों में निफ्टी 100 टीआरआई से बेहतर प्रदर्शन किया है।

नया निवेश मौका

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एनएफओ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड (18 नवंबर से 2 दिसंबर, 2024 तक निवेश के लिए खुला), कम अस्थिरता के साथ इक्विटी एक्सपोजर प्रदान करता है। मजबूत गर्वनेंस और नकदी प्रवाह वाले लार्ज-कैप स्टॉक पर केंद्रित, इसका लक्ष्य विविध, कम-अस्थिरता रणनीतियों के माध्यम से लॉन्गटर्म कैपिटल ग्रोथ है।

यह योजना लो-वैरिएंस वाले स्टॉक को हाई-वेटेज देकर प्राथमिकता देती है, जबकि उच्च अस्थिरता वाले स्टॉक को कम भार दिया जाता है। व्यापक विश्लेषण पर आधारित स्टॉक चयन को बढ़ावा देता है, जिसमें पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स बाजार की अलग अलग पहलुओं से जुड़ा होता है। लक्ष्य एक विविध पोर्टफोलियो बनाना है जो अस्थिरता को कम करते हुए लॉन्गटर्म ग्रोथ सुनिश्चित करता है।

भारत देश में क्यों आवश्यक है "समान नागरिक संहिता"

परिवहन विशेष न्यूज

एक मित्र ने पेंशन कार्यालय का दौरा किया और सरकारी पेंशन अधिकारी ने जो बताया, उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मित्र ने अधिकारी से पूछाः आप एक सेवानिवृत्त मुस्लिम कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी चार पत्नियों के बीच पेंशन कैसे वितरित करते हैं? अधिकारी ने बतायाः ₹हम नामांकन विवरण का संदर्भ लेते हैं। पेंशन प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार वितरित की जाती है। यदि कोई नामांकन नहीं है, तो हम इसे सभी चार पत्नियों के बीच समान रूप से विभाजित करते हैं, प्रत्येक को 25% आवंटित करते हैं।

यहाँ है ट्विस्टः

हिंदुओं के मामले में, अगर किसी व्यक्ति की एक पत्नी है और वह मर जाती है, तो पेंशन बंद हो जाती है। लेकिन मुसलमानों के मामले में, पेंशन तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी चार पत्नियाँ एक के बाद एक मर न जाएँ।

जाने यह कैसे काम करता हैः

यदि कोई नामांकन नहीं होता है तो चारों पत्नियों में से प्रत्येक को 25% हिस्सा मिलेगा। जब एक पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो शेष तीन को 33.33% हिस्सा मिलता है। जब दूसरी पत्नी गुजर जाती है, तो शेष दो को 50-50% मिलता है। जब तीसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो चौथी पत्नी को उसकी मृत्यु तक 100% पेंशन मिलती है।

अब इस पर विचार कीजियेः

पहली पत्नी 60 वर्ष की है। दूसरी पत्नी 50 वर्ष की है। तीसरी पत्नी 40 वर्ष की है। चौथी पत्नी 30 वर्ष की है। यदि दोनों 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो सामूहिक रूप से पेंशन 10 + 20 + 30 + 40 = 100 वर्ष के लिए ली जाएगी। मुस्लिम में सबसे छोटी पत्नी को अकेले 40 वर्ष तक पेंशन मिल सकती है। इसके विपरीत, अन्य धर्मों के व्यक्तियों की पत्नियों को केवल 10 वर्षों के लिए पेंशन मिल सकती है। मुस्लिम विधवाओं को काफी लाभ मिलता है, और करदाता इसका खर्च वहन करते हैं।

यह कोई असामान्य बात नहीं है कि 30 वर्षीय मुस्लिम महिला 90 वर्षीय पुरुष से विवाह कर ले, जो पेंशन पाने के बारे में स्पष्ट रूप से सोचता हो। इससे पुरानी सरकारी नीतियों की खामियां और व्यवस्था में गिरावट का स्तर उजागर होता है।

कानूनी सुधार की सख्त जरूरत है।

जब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे सुधार प्रस्तावित किए जाते हैं, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए उनका विरोध करते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि ऐसे परिवर्तनों का विरोध कौन करता है, और समुदाय के हितों को कभी न भूलें। ₹समान नागरिक संहिता₹ सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन कई लोग अपने राजनीतिक एजेंडे की सुरक्षा के लिए इसका विरोध करते हैं।

उत्तराखंड में वाहनों की आयु सीमा लागू, सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

इशिका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड न्यूज
परिवहन विशेष

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से वाहनों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत, मैदानी क्षेत्रों में 18 वर्ष और पहाड़ी क्षेत्रों में 15 वर्ष पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह कदम राज्य में बढ़ते सड़क हादसों को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है।

नवीनतम अपडेट्सः

- *व्यावसायिक वाहनों के लिए आयु सीमाः* कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के लिए शहरी क्षेत्रों में 10 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है।
- *निजी वाहनों के लिए आयु सीमाः* मैदानी क्षेत्रों में 18 वर्ष और पर्वतीय क्षेत्रों में 15 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी।

यह निर्णय विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया गया है। पुराने और तकनीकी रूप से कमजोर वाहनों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी। परिवहन उपायुक्त दिनेश पठोई ने कहा कि एसटीए की अगली बैठक से पहले मॉडल सीमा का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा।

वाहन मालिकों के लिए नई शर्तेंः

रूट परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद वाहन मालिक उसी रूट पर वाहन का संचालन नहीं कर सकेंगे। हालांकि, वे किसी अन्य रूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नीति वाहनों के संचालन में पारदर्शिता लाने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

इस नई नीति से जहां पुराने वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों को बदलने की आवश्यकता होगी, वहीं यात्रियों को भी अधिक सुरक्षित और बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पर्यावरणीय प्रदूषण को भी नियंत्रित करेगा, क्योंकि पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।

संस्कृति और इतिहास बचाने के लिए डैमोग्राफी को बचाना क्यों जरूरी?

मनोज कुमार अग्रवाल-विभूति फीचर्स

हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट (प्रजनन दर में गिरावट) पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे गिर जाती है, तो वह समाज धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है। भागवत ने यह बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने जनसंख्या नीति को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। भागवत ने कहा, ₹आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है, तो वह समाज दुनिया से नष्ट हो जाता है। वह समाज तब भी नष्ट हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता है। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए हैं। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए।₹ उन्होंने यह भी कहा कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को दो से अधिक बच्चों की आवश्यकता है, इस तरह उन्होंने तीन बच्चों की जरूरत पर जोर दिया। जनसंख्या विज्ञान भी यही कहता है कि यह संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का बने रहना जरूरी है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश को उस कड़वे सत्य से परिचित कराने का प्रयास किया है जिसका हिन्दू समाज अपनी उदासीनता के कारण सामना नहीं करना चाहता। मोहन भागवत ने 2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट को सम्मुख रख अपनी चिंता प्रकट की है। लेकिन धरातल का सत्य है कि 1901 से 2001 के जनसंख्या आंकड़ों पर ध्यान दें तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इतिहास में जाए तो अफगानिस्तान तक भारत था और यहां हिन्दू राजाओं का ही राज था। 1947 में जनसंख्या में आए बदलाव के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था।

विश्व पर नजर दौड़ाएं तो आपको संघ प्रमुख भागवत की चेतावनी व चिंता का कारण समझ आ जाएगा। विश्व के जिस क्षेत्र में ईसाई या मुस्लिम जनसंख्या बहुमत में आई है वहां की संस्कृति ही बदल गई वहां की मूल संस्कृति और इतिहास सब कुछ लुप्त हो गया।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस समस्या को लेकर चिंता प्रकट की है अतीत में उसी को पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने विभिन्न ढंग से कहा है₹ मुसलमान भारत पर 'राजनीतिक श्रेष्ठता' स्थापित करने के विचार को लेकर चलते हैं। अतः यह न धार्मिक समस्या है और न सामाजिक, यह तो सीधी राजनीतिक समस्या है।"

भारत में इस्लाम मौलवी या फकीरों के प्रचार के द्वारा नहीं आया, अपितु यह आक्रमणकारियों के द्वारा आया। सूफी फकीरों ने एक सोची समझी साजिश के तहत धर्मभीरू अंधविश्वासी आमजन को कनवर्जन के लिए नरम रुख दिखाया ताकि जोर-जबरदस्ती के साथ ही लचीला रुख दर्शा कर भी हिन्दू समाज को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा सके। हिन्दुस्तान में ये आक्रान्ता लोग अपने आपको देश का मालिक समझने लगे। जो व्यक्ति हिन्दुस्तान में कनवर्जन कर मुसलमान बना, वह भी अपने आपको आक्रान्ताओं से जोड़कर देखने लगा और यहां की प्रत्येक विरासत से घृणा करने लगा। बाबर भारत में आक्रान्ता बतौर आया। यहां का एक बड़ा वर्ग खुद को देश की मूल सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत से अलग कर उससे नफरत करने लगा इसका परिणाम मुसलमान के अन्तः करण में आज तक है। इस कारण यदि हम उसे कहें कि इस भूमि को भारत माता कह तो वह मानता नहीं। इसे माता न मानने के कारण ही पाकिस्तान बना। हमने कहा राम और कृष्ण अपने पूर्वज हैं, परन्तु वह इन्हें अपना पूर्वज न मानकर अलग से दूसरे पूर्वजों को मानता है। इसलिए यह कहना पड़ता है कि यहां का मुसलमान राष्ट्रीय नहीं। हिन्दुस्तान विरोधी जो-जो चीजें होंगी, वह उनको ही अपनाता है। हमने भारत को मां कहा, परन्तु वह इसे दारूल हरब कहता है। हम गाय की पूजा करते हैं, परन्तु वह उसको काटता है। भारत में वह बकरीद कहकर त्यौहार मानता है। बकर का अर्थ अरबी में गाय होता है अर्थात्‌ जो गाय हमारे लिए पूजनीय है, वह इस त्यौहार पर बलि दी जाती है। यह हमारी श्रद्धा के विरुद्ध है।

देश में लगातार बहुसंख्यक वर्ग की जनसंख्या दर में गिरावट और एक खास अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। यह भारत की डैमोग्राफी के लिए खतरनाक हो सकता है।

हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कह दी कि इसके लिए जरूरी है कि 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें। यह संख्या इसलिए जरूरी है, ताकि समाज जिंदा रहे। मोहन भागवत ने नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में एक सभा में बोलते हुए कहा, कुटुंब समाज का हिस्सा है और हर परिवार एक इकाई है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए सालों से 'बच्चे 2 ही अच्छे' का नारा सरकार की तरफ से लगाया जाता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक 'आदर्श हंदिू परिवार' को कतिने बच्चे पैदा करने चाहिए? जानिए सनातन धर्म में इसके बारे में क्या कहा गया है।

मोहन भागवत से पहले प्रसिद्ध कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जबलपुर में एक कथा के दौरान कहा था कि 'हंदिुओं को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए।' वहीं कुछ धर्म गुरु महलिाओं को कम से कम 4-4 बच्चे पैदा करने की बात कह चुके हैं। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामीश्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस सवाल के जवाब में कहा, 'हमारे यहां 'बहु पुत्रवति भव' ये आशीर्वाद हमेशा से दयिा जाता है। 'बहु' का मतलब होता है बहुवचन। हंदिी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, यानी दो भी हो तो वो बहुवचन हो जाता है लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्वविचन और बहुचन होते हैं। यानी तीन होने पर ही उसे बहुवचन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि तीन तो होने ही चाहिए। बहु पुत्रवति में 'बहु' शब्द इसी बात को दर्शाता है।' शंकराचार्य सोशल मीडयिा पर डाले गए अपने इस वीडयिो में आगे कहते हैं, 'हमारे यहां पहले नयिोजन (प्लानगिं) नहीं कयिा जाता था। ये माना जाता था कि सहज में जब गर्भ धारण हो जाए तो संतान को जन्म लेने का अधकिार देना चाहिए। अब ऐसी परिस्थर्ति हो रही है कि गर्भधारण तो हो रहा है, लेकिन उसकी भ्रूण हत्या की जा रही है। शास्त्रों में भ्रूण हत्या को मनुष्य की हत्या के समान ही माना गया है। सबसे पहले तो सनातनी दंपत्ति को भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए।' वह आगे कहते हैं, 'अगर धार्मिक दृष्टकिोण से देखें तो जतिने भी पुत्र या पुत्रयिां हों, वह सब स्वागत के योग्य होते हैं।'

हालांकि, मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि मोहन भागवत पिछले कुछ समय से जब कुछ बोलते है तो वह बीजेपी को असहज कर देता है। पिछली बार भी जब मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना तब भी बीजेपी वाले जो केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी पूरे देश में जनसंख्या को लेकर केवल राजनीति करने का काम कर रही है, सपा समझती है कि मोहन भागवत के बयान के बाद अब बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। सपा की विचारधारा भले आरएसएस से न मिलती हो लेकिन अगर कुछ उन्होंने सही कहा है तो सही को सही कहना गलत नहीं है।

मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मोहन भागवत से सवाल करते हुए कहा कि, 'जो पहले से हैं उनको तो नौकरियां दिलवा दो, नौकरियां है नहीं, फसल की ज़मीन कम हो रही हैं। मोहन भागवत चाहते हैं कि दो से ज्यादा बच्चे हों। देश में वैसे ही बेरोज़गारी है, जो आज युवा हैं उनको तो नौकरियां मिल नहीं पा रही, फसल की जमीन कम होती जा रही है जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चीन ने जब आबादी कम की तब वो आज महाशक्तिशाली बना है। मोहन भागवत चीन से सीख नहीं ले पा रहे और वो जनसंख्या के मामले में देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मेरा तो उनको सुझाव है कि मोहन भागवत हैं, पीएम मोदी हैं, यूपी के सीएम योगी हैं तो सबसे पहले ये शुरुआत करें अगर इन्हें जनसंख्या की इतनी चिंता है तो, इनसे शुरुआत होनी चाहिए।

महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के जनसंख्या बढ़ाने संबंधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाटिल ने कहा कि पहले अजित पवार ने राज्य विधानसभा में एक बिल पेश किया था, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो वह स्थानीय निकाय चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। जयंत पाटिल ने उम्मीद जताई कि अब नई सरकार इस कानून में बदलाव करने की दिशा में कदम उठाएगी और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी, जिनके ज्यादा बच्चे हों।

असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, मोहन भागवत ने कहा कम से कम तीन बच्चे पैदा करिये। मोहन भागवत साहब आप लोग कब शादी कर रहें हैं पहले वो बताइये। मोदीजी ने कहा था कि आपका मंगलसूत्र छीन कर उन महिलाओं को दिया जायेगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। उनका इशारा मुस्लिम महिलाओं की तरफ था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है की बच्चे ज्यादा पैदा करो।

भागवत के बयान के बाद जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर देशभर में बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि संघ प्रमुख ने इसे समाज के अस्तित्व से जोड़ते हुए जनसंख्या नीति पर ध्यान केंद्रित किया हैं। (विभूति फीचर्स)

ममता महंत के फॉर्मूले में सुजीत फिर जाएंगे सकते राज्यसभा : पूर्ब केंद्रीयमंत्री बिस्वेश्वर टुडू

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है और राज्यसभा में कौन जाएगा, इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने बड़ा बयान दिया है। बिश्वेश्वर ने कहा कि बीजेपी ममता महंत के फॉर्मूले के आधार पर सुजीत कुमार को राज्यसभा भेज सकती है और राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मीडिया को जवाब देते हुए विश्वेश्वर ने कहा, 'बहुत सारी चर्चाएं होंगी। उन्हें लगता है कि ममता महंत के फॉर्मूले में सुजीत कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा। हालाँकि, चूंकि यह पूर्ण अवधि का कार्यकाल नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि सुजीत कुमार ममता महंत की तरह राज्यसभा जाएंगे, बिश्वेश्वर टुडू ने कहा। हालांकि, विश्वेश्वर ने कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला महतपूर्ण है। बता दें कि बिजेड़ी से राज्यसभा गए सुजीत कुमार ने 6 सितंबर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और राज्यसभा सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया था। और पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दिल्ली में बीजेपी का हाथ थाम लिया। तब से यह राज्यसभा सीट खाली है। इसीलिए आज उपचुनाव की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक आज से अगले 10 तारीख तक नामांकन पत्र जमा किये जायेंगे। 11 को प्रत्याशियों की जांच होगी जबकि 13 को नाम वापसी होगी। इसी तरह 20 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गयी है। हालांकि, सुजीत कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई यह राज्यसभा सीट संख्या के लिहाज से सत्तारूढ़ बीजेपी के खाते में जाना तय है। हालांकि, खाली हुई सीट पर राज्यसभा में कौन जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच विश्वेश्वर के इस बयान ने चर्चा को हवा दे दी है।

मोरारी बापू की रामकथा में बुजुर्गों की सेवा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के काम के लिए आगे आए समाजसेवी

यह रामकथा भगवान राम और रामायण की शिक्षाओं से समाज को उन्नत करने की मोरारी बापू की छह दशक की यात्रा में 947वीं कथा थी। सत्य प्रेम और करुणा के उनके शाश्वत संदेश से दुनिया भर में करोड़ों श्रद्धालु उत्साह से जुड़ते हैं। राजकोट के इस आयोजन ने तो आध्यात्मिकता की समाज में क्रांति लाने की शक्ति को और अधिक उद्घाटित किया है।

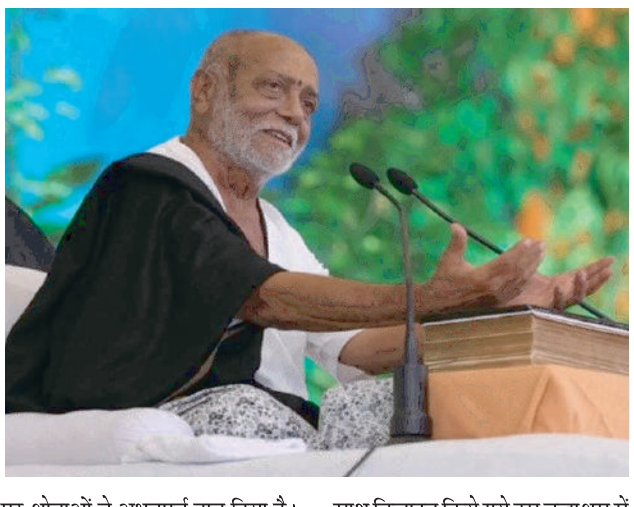

राजकोट में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और रामचरितमानस के प्रखर प्रवर्तक मोरारी बापू की रामकथा में बुजुर्गों की सेवा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के महान कार्य के लिए 60 करोड़ रुपए से अधिक के दान की गंगा बही है। दान की राशि सद्भावना ट्रस्ट द्वारा बनाये जाने वाले वृद्धाश्रम तथा अन्य धर्मार्थ कार्यो के लिए दी जायेगी।

राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में आयोजित रामकथा के पहले ही दिन मोरारी बापू ने लोगों से बुजुर्गों और प्रकृति के प्रति अपना स्नेह और समर्थन व्यक्त करने की अपील की थी। उनके आह्वान पर श्रोताओं ने अभूतपूर्व दान दिया है। इतने बडे. दान से रामकथा के करुणा और मानवता के मूल संदेश को भी बल मिला है।

जामनगर रोड पर पडधरी में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सद्भावना वृद्धाश्रम के लिए दान प्राप्त करना ही इस कथा का एक मुख्य उद्देश्य है। निराश्रित, विकलांग और असहाय बुजुर्गों कों अपना घर मिले इस लक्ष्य के साथ डिज़ाइन किये गये इस वृद्धाश्रम में कुल 1,400 कमरे होंगे जहां बुजुर्गों की पूरे सम्मान के साथ देखभाल की जायेगी। इस प्रोजेक्ट का दूसरा उद्देश्य बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण भी है, जो आध्यात्मिक मूल्यों के साथ पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को जोड़ता है।

यह रामकथा भगवान राम और रामायण की शिक्षाओं से समाज को उन्नत करने की मोरारी बापू की छह दशक की यात्रा में 947वीं कथा थी। सत्य, प्रेम और करुणा के उनके शाश्वत संदेश से दुनिया भर में करोड़ों श्रद्धालु उत्साह से जुड़ते हैं। राजकोट के इस आयोजन ने तो आध्यात्मिकता की समाज में क्रांति लाने की शक्ति को और अधिक उद्घाटित किया है।

भव्य पोथी यात्रा के साथ आरंभ हुई इस पुण्यकथा का लाभ प्रतिदिन लगभग 80,000 से अधिक भक्त, गणमान्य लोगों और स्वयंसेवकों ने लिया है। साथ ही प्रतिदिन बड़ी संख्या मे श्रोताओं और भक्तजनो ने भावपूर्वक भोजनप्रसाद का ग्रहण भी किया। इस आयोजन को सफल बनानें के लिए दर्जनों सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों ने रात -दिन एक किया है। 1 दिसंबर को पूर्ण हुई रामकथा ने हजारों लोगों में दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति के साथ आस्था की सार्थक सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाने वाली क्षमता को भी प्रकाशित किया है। एकत्रित धनराशि सैकड़ों निराधार वृद्धों के लिए आशा की किरण लाने के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भी योगदान देगी।

क्यों? यूँ जताते हो अपनी नाराजगी

क्यों? यूँ जताते हो अपनी नाराजगी,
जब लौटकर महायुती में ही आना है।
क्या? ये बीमारी भी एक बहाना है,
फिर लौटकर इसी घर ही आना है!
अपरिपक्व कह रहा यह जमाना है।

क्यों? यूँ जताते हो अपनी नाराजगी,
जब लौटकर महायुती में ही आना है।
अब न जाना सतारा नेटवर्क है खटारा,
वे दिल्लीवाले हैं अब न खोलेंगे पिटारा!
मुश्किल में पाओगे अजब ही है नज़ारा।

क्यों? यूँ जताते हो अपनी नाराजगी,
जब लौटकर महायुती में ही आना है।
छोड़ दो जिद अब नहीं रही है वह बात,
उनका प्रचंड है बहुमत छूट जाएगा साथ!
ऐसा ना हो कहीं मलते रह जाओ हाथ।

क्यों? यूँ जताते हो अपनी नाराजगी,
जब लौटकर महायुती में ही आना है।
सोच लो, अगर यही रवैया रखना है,
नेता बनकर खुद को भी परखना है!
हा रिक्त है नेता प्रतिपक्ष का भी स्थान,
उस पर हो जाओ एकनाथ विराजमान।

संजय एम. तराणेकर

कानपुर में जारी हत्याओं का दौर, बुजुर्ग किसान की हत्या कर शव कुएं में फेंका

- बटाईदार को छोड़ने जाने के बाद घर वापस नहीं लौटा बुजुर्ग किसान, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

सुनील बाजपेई

कानपुर। इस महानगर में आजकल हत्याओं का दौर सा चल रहा है बीते तीन माह के अंदर आधा दर्जन लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इसी क्रम में बिधनू थानाक्षेत्र में भी पत्थर से सिर कुचलकर एक बुजुर्ग किसान की हत्या कर दी गई। उसकी लाश कुएं से बरामद किए जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस हत्यारे की तलाश में लगातार जुटी हुई। यद्यपि घटना की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैलेकिन प्रथम दृष्टया इसकी वजह पुरानी रंजिश से जुड़ी बताई जाती है। पुलिस इस बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है।

घटना के बारे में प्राप्त विवरण के मुताबिक कठुई गांव निवासी किसान सरोज कुमार कुशवाहा अपने बटाईदार को छोड़ने उसके घर गए थे। जिसके बाद से सरोज कुमार वापस घर नहीं लौटे, रात भर कई जगह पर उनकी खोजबीन कराई गई। सुबह ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली कि उनका शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा हुआ है। जहां बड़ी संख्या में गांव वालों के साथ पहुंचे परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सिर पर भारी पत्थर से वार कर हत्या की है। इसके बाद परिजनों ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। बाद में मौके पर थाना पुलिस के साथ एडीसीपी साउथ, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड भी पहुंचे। इस बीच डॉग स्क्वॉयड काफी देर तक गांव के आसपास घूमता रहा। एडीसीपी साउथ महेश कुमार ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच कर घटना का सटीक खुलासा जल्द किया जायेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023